My Notes....

राष्ट्रीय

'भारत रैंकिंग 2017' जारी किया

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में शैक्षिक संस्थानों के लिए 'भारत रैंकिंग 2017' जारी किया और इसे देश को समर्पित किया। यह कदम पूरे देश के छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में परिवर्तन लाने की हमारी सरकार की प्रतिबद्धता की अगली कड़ी है जिसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। इस रैंकिंग से संस्थाओं के बीच उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु उचित प्रतिस्पर्धा की शुरुआत होती है। इससे हमने किसी भी संदेह से परे सफलता अर्जित की है और आगे बढ़ने के लिए बाध्य भी है।

क्या है

1. मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी रैंकिंग चार्ट पर किसी ने भी उंगली नहीं उठाया है और यह निर्धारित मूल्यों पर अपने को सही साबित कर दिखाया है।
2. आज तक एनएएसी और एनबीए का शैक्षिक संस्थानों के आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता था लेकिन अब हमारी सरकार ने पारदर्शिता और विश्वसनीयता लाने के लिए एक अद्वितीय परिवर्तन किया है।
3. स्थानों के अलावा अब माता-पिता और छात्रों को भी किसी विशेष विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या व्यावसायिक संस्थान की रैंकिंग और गुणवत्ता के बारे में जानकारी भी मिलेगी। इससे हमारे प्रत्यय पत्र की वैश्विक स्केलिंग बढ़ गई है।
4. इस अवसर पर मंत्री जी ने घोषणा किया कि सरकार गुणवत्ता प्रदान करने वाले शिक्षा संस्थानों को अधिक सहायता प्रदान करेगी। यह नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है और इससे सभी संस्थानों को अपना प्रदर्शन और उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा।
5. प्रस्तुत किए गए शोध पत्रों की संख्या, प्राप्त पेटेंट और परिसर प्लेसमेंट के आंकड़े भी सरकारी सहायता पाने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक धारणा, नियोक्ता की धारणा और शैक्षिक धारणा को भी महत्व प्रदान किया जाएगा।
6. उच्च शिक्षा सचिव श्री के के शर्मा ने श्भारत रैंकिंग 2017श पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि रैंकिंग के इस दूसरे संस्करण में कुल 2995 संस्थानों ने भाग लिया है।
7. इसके अंतर्गत 232 विश्वविद्यालयों, 1024 प्रौद्योगिकी संस्थानों, 546 प्रबंधन संस्थानों, 318 फार्मेसी संस्थानों तथा 637 सामान्य स्नातक महाविद्यालयों और अन्य शामिल हैं।
8. एनआईआरएफ पांच व्यापक मापदंडों के आधार पर संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करता है. इनमें शिक्षण-अधिगम संसाधन, अनुसंधान एवं व्यावसायिक प्रक्रियाएं, पहुंच एवं समावेशिता, अवर स्नातक परिणाम और अवधारणा जैसे मानक शामिल हैं.

शीर्ष यूनिवर्सिटी

1. भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर
2. जवाहरहल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली
3. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
4. जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बैंगलोर

टॉप 10 कॉलेज

1. मिरांडा हाउस कॉलेज, नई दिल्ली
2. लोयला कॉलेज, कॉलेज
3. श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली
4. हेबर कॉलेज, तिरूचिरापल्ली
5. आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज, नई दिल्ली
6. सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता
7. लेडी श्रीराम कॉलेज, नई दिल्ली
8. दयाल सिंह कॉलेज, नई दिल्ली
9. दीन दयाल उपाध्योय कॉलेज, नई दिल्ली

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

10. वुमन क्रिश्चियन कॉलेज, चेन्नई

मैनेजमेंट संस्थान

1. भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद
2. भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलूर
3. भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता
4. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ
5. भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझिकोड
6. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली - प्रबंधन स्कूल
7. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर-प्रबंधन स्कूल
8. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की-प्रबंधन स्कूल

रेल विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी

केंद्र सरकार ने रेल विकास प्राधिकरण (आरडीए) के गठन को मंजूरी दे दी है। आरडीए रेल किराये-भाड़े के अलावा रेल सेवाओं की गुणवत्ता के मानक तय करने तथा रेलवे तथा ग्राहकों बीच कीमत व प्रतिस्पर्धा संबंधी मसलों के समाधान का काम करेगा। सिफारिश देने वाला निकाय होने के कारण इसकी सिफारिशें मानना रेलवे के लिए जरूरी नहीं होगा। आरडीए एक स्वतंत्र नियामक होगा जिसमें अध्यक्ष के अलावा तीनों क्षेत्रों से संबंधित तीन विशेषज्ञ सदस्य होंगे। इनका पांच साल का तयशुदा कार्यकाल होगा। अध्यक्ष की नियुक्ति निजी क्षेत्र से भी की जा सकती है, जिसका चयन कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। इसका गठन 50 करोड़ रुपये के कोष के साथ होगा।

ऐक्ट में संशोधन नहीं होगा

1. कैबिनेट ने इस अथॉरिटी के गठन के लिए जो प्रस्ताव पारित किया है, उसके मुताबिक इस अथॉरिटी के गठन के लिए रेलवे ऐक्ट में कोई संशोधन नहीं होगा बल्कि सरकार एक एक्जिक्यूटिव ऑर्डर के जरिये इस अथॉरिटी को बनाएगी।
2. इस फैसले से अब होगा यह कि यह अथॉरिटी खर्चों और आमदनी का जायजा लेने के बाद रेल किराये में बढ़ोतरी की सिफारिश ही कर सकेगी। इसके बाद सरकार उस सिफारिश पर फैसला लेगी। ऐसे में अंततः रेल किराये के बारे में फैसला करने का अधिकार सरकार के पास ही होगा।

क्या होगा फायदा?

1. अथॉरिटी के गठन का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे रेल यात्रियों को प्रोटेक्शन मिलेगा और अथॉरिटी यात्रियों को मिलने वाली सर्विस का मापदंड तय करेगी। इस तरह से सर्विस की क्वॉलिटी में सुधार हो सकता है। मसलन, ट्रेनों की लेटलतीफी को लेकर अथॉरिटी कड़ा रुख अपना सकती है और यात्रियों को मुआवजा भी दे सकती है।
2. अथॉरिटी के गठन से एक फायदा यह होगा कि रेलवे में प्राइवेट प्लेयर्स भी आ सकेंगे। लगभग उसी तरह से हालात हो सकते हैं, जैसे टेलिकॉम में हुआ है। पहले सरकारी कंपनी एमटीएनएल थी, लेकिन बाद में प्राइवेट कंपनियां भी इस सेक्टर में आई। अब रेलवे में भी प्राइवेट प्लेयर आ सकेंगे।
3. दरअसल, अब तक चिंता यह थी कि अगर प्राइवेट कंपनी आए तो उसे रेलवे की अफसरशाही से जूझना पड़ता, लेकिन रेग्युलेटरी अथॉरिटी आने से रेलवे अफसरों की मनमानी खत्म हो सकेगी और प्राइवेट कंपनियों को भी बराबरी का मौका मिलेगा। इसी तरह से रेलवे में

अथॉरिटी कैसे बनेगी?

1. इस अथॉरिटी में एक चेयरमैन और तीन सदस्य होंगे। अथॉरिटी चाहेगी तो एक्सपर्ट्स की सलाह भी ले सकेगी। अथॉरिटी के चेयरमैन का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।
2. चेयरमेन और सदस्यों का चयन करने के लिए सर्च कमिटी होगी और इस कमिटी में कैबिनेट सेक्रेटरी के अलावा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, कार्मिक मंत्रालय के सचिव ओर किसी अन्य रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक चेयरमैन भी होगा।
3. अथॉरिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया गया है। रेलवे के अफसरों का कहना है कि टारगेट रखा गया है कि एक अगस्त से यह अथारिटी काम करना शुरू कर दे।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। इसका नतीजा यह भी होगा कि रेलवे में प्राइवेट निवेश बढ़ेगा। जाहिर है कि इससे रेलवे के कामकाज में भी सुधार की उम्मीद बंधेगी।

भारत में बीएस-IV ईंधन की बिक्री शुरू

भारत में औपचारिक तौर बीएस-IV ग्रेड के ईंधन की लॉन्चिंग कर दी गई। इसका उदेश्य देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करना और 2020 तक बीएस-VI ईंधन को लागू करने का रास्ता तैयार करना है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत में बीएस-III वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर 1 अप्रैल से रोक लगाने के कुछ दिन बाद बीएस-IV ईंधन की लॉन्चिग की गई है।

क्या है

1. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के स्थापना दिवस उत्कल दिवस के अवसर पर बीएस IV ईंधन की शुरुआत की। प्रधान ने प्रतीकात्मक रूप से इको-फ्रेंडली ईंधन की बिक्री की शुरुआत की। लाइव विडियो लिंक के द्वारा देश के अलग-अलग 12 जगहों से इस ईंधन की बिक्री की शुरुआत हुई।
2. वाराणसी, विजयवाड़ा, दुर्गापुर, गोरखपुर, इंफाल, भोपाल, रांची, मदुरै, नागपुर, पटना, गुवाहाटी और शिलांग में इस ईंधन की बिक्री शुरू हो गई है।
3. इस अवसर पर प्रधान ने कहा, श्आज हमने साफ-सुथरे परिवहन के एक युग की शुरुआत की है।
4. इससे देश के 125 करोड़ लोगों को फायदा होगा क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण में कमी आएगी।

एशिया की सबसे लंबी सुरंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर एशिया की सबसे लंबी चनैनी-नाशरी टनल का उद्घाटन किया। जम्मू से कश्मीर घाटी जाने वाले वाहनों को इस टनल से गुजरना काफी सस्ता पड़ेगा क्योंकि पहले चनैनी से नाशरी तक के 41 किमी लंबे रास्ते काफी टेढ़े मेढ़े और जबरदस्त चढ़ाई वाले थे जिस पर वाहन चलाना काफी मुश्किल होता था। साथ में औसतन तीन लीटर पेट्रोल खर्च भी होता था लेकिन अब यह सफर मात्र 55 रुपये में होगा। इससे महीने में करीब 30 लाख रुपये ईंधन की बचत होगी।

क्या है

1. यह एक ऐसा टनल है, जिसके भीतर और बाहर 124 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। हर कैमरे की दूरी 75 मीटर है। ये 360 डिग्री घूमने वाले कैमरे हैं।
2. सुरंग के अंदर घुटन महसूस न हो इसलिए इसे पूरी तरह हवादार बनाया गया है, साथ ही निगरानी के लिए संचार व्यवस्था का दुरुस्त इंतजाम किया गया है।
3. इस टनल की लबाई है 9.2 किलोमीटर। विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में आरएफएंडएफएस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लिमिटेड ने देश की सबसे बड़ी सड़क परिवहन टनल का निर्माण रिकॉर्ड साढ़े चार साल में किया है।
4. इसका नाम चनैनी-नाशरी टनल रखा गया है क्योंकि यह जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चनैनी से शुरू होकर नाशरी नामक स्थान पर जाकर खुलती है।
5. 286 किलोमीटर लंबी जम्मू-श्रीनगर चार लेन राजमार्ग वाली परियोजना का यह हिस्सा 9.2 किलोमीटर लंबी दोहरी ट्यूब सुरंग पर 23 मई 2011 मे शुरू हुआ। इस सुरंग मार्ग पर 3,720 करोड़ रुपए की लागत आई है।
6. 1200 मीटर की ऊंचाई पर बने इस सुरंग में दो समानातंर ट्यूब हैं। मुख्य ट्यूब का व्यास 13 मीटर है और सुरक्षा ट्यूब या निकास ट्यूब का व्यास छह मीटर है। दोनों ट्यूब में 29 जगहों पर क्रॉस पैसेज है। मुख्य ट्यूब में हर 8 मीटर पर ताजा हवा के लिए इनलेट बनाए गए हैं। हवा बाहर जाने के लिए हर 100 मीटर पर आउटलेट बनाए गए हैं।
7. सुरंग में हर 150 मीटर पर एसओएस बॉक्स लगे हैं। आपातकालीन स्थिति में यात्री इनका इस्तेमाल हॉट लाइन की तरह कर सकेंगे। आईटीसीआर से मदद पाने के लिए यात्रियों को एसओएस बॉक्स खोलकर बस 'हैलो' बोलना होगा।
8. एसओएस बॉक्स में फर्स्ट एड का सामान और कुछ जरूरी दवाएं भी होंगी ताकि किसी तरह का हादसा होने पर उन्हें तुरंत जरुरी मदद मिल सके।

उपग्रह निर्माण हेतु निजी क्षेत्र के साथ अनुबंध

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation-ISRO) ने उपग्रह निर्माण का काम आउटसोर्स करके निजी क्षेत्र के साथ हाथ मिलाया है। इसरो ने उपग्रह निर्माण की गति के साथ सामंजस्य बैठाने और इस दिशा में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिये निजी क्षेत्र के साथ अनुबंध किया है।

क्या है

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

1. लगभग 150 मिशन और तीन दशकों के अंतरिक्षीय कार्य के बाद, इसरो का यह एक अभूतपूर्व अभियान है।
2. इसके लिये बेंगलुरु के एक हाईटेक रक्षा उपकरण आपूर्तिकर्ता अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज (Alpha Design Technologies) को पहले निजी उद्योग के तौर पर चुना गया है।
3. भारत को उसका पहला बड़ा निजी उपग्रह दिलाने के लिये इसरो ने 400 करोड़ रूपए की कंपनी अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज के साथ यह करार किया है।
4. इस अभियान में निजी क्षेत्र के दल, सरकारी इंजीनियरों के साथ मिलकर पूर्ण नेविगेशन उपग्रह बनाने का काम कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत 70 इंजीनियरों का दल आगामी छह महीने में उड़ान भरने योग्य उपग्रह बनाने के लिये कार्यरत है।
5. यह बिलकुल नई किस्म की जुगलबंदी है क्योंकि यह पहला अवसर है, जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने, कई करोड़ रुपए के उपग्रह को बनाने के लिये निजी क्षेत्र के किसी उद्योग की मदद ली है।
6. अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज, बेंगलुरू के नेतृत्व वाले एक संघ (Consortium) को भारत के नेविगेशन तंत्र के लिये दो पूर्ण उपग्रह बनाने का काम दिया गया है।

मोटर विधेयक लोकसभा में पारित

दुर्घटना मुआवजा समेत अनेक मुद्दों पर विपक्ष के संशोधनो को खारिज करते हुए सरकार आखिर लोकसभा में मोटर वाहन संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित कराने में कामयाब हो गई। अब इसे केवल राज्यसभा की दीवार पार करना शेष है। सरकार के इरादों को देखते हुए लगता है वह वहां भी इसे येन-केन-प्रकारेण पास करा लेगी। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ज्यादातर वही बातें दोहराई जो बिल पेश करते वक्त कही थीं। दुर्घटना में मौत की स्थिति में पांच लाख रुपये का मुआवजा तुरंत तथा अधिकतम दस लाख रुपये का मुआवजे देने के प्रावधान पर उनका तर्क था कि पांच लाख से संतुष्ट न होने वाले पीडितों के लिए ज्यादा मुआवजा पाने का रास्ता खुला रहेगा।

क्या है

1. ज्यादातर पीडित बीमा कंपनियों के दबाव में झंझट से बचने के लिए पांच लाख मुआवजे पर राजी हो जाएंगे खास मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल या अदालत के समक्ष ज्यादा मुआवजे के लिए अपील नहीं करेंगे। अभी ट्रिब्यूनल या त की आर्थिक स्थिति के अनुसार मुआवजे का निर्धारण करती हैं जो पचास लाख या करोड़-दो करोड़ भी हो सकता है।
2. इसी आधार पर मुआवजे की अधिकतम सीमा को दस लाख से बढ़ाकर 20 लाख किए जाने के लिए माकपा सांसद शंकर प्रसाद दत्ता ने संशोधन भी पेश किया था।
3. लेकिन वोटिंग में वह 37 के मुकाबले 221 मतों से रद हो गया। गडकरी ने कहा कि मुआवजे को 20 लाख करना संभव नहीं होगा क्योंकि इससे इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। लेकिन विशेषज्ञ और कई विपक्षी दल इससे सहमत नहीं हैं और वे राज्यसभा में संशोधन पर अड़ सकते हैं। राज्यसभा में सरकार बहुमत में नहीं है।
4. विधेयक में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्मानों के अलाव तों की मदद करने वाले भले मानुसों की सुरक्षा करने व उन्हें पुलिस के उत्पीड़न से बचाने तथा घटिया व त्रुटिपूर्ण वाहन बनाने वाले निर्माताओं की जवाबदेही तय करने जैसे नए प्रावधान हैं।
5. बिल का बुनियादी मकसद मानव जीवन की रक्षा करना है। क्योंकि हर साल पांच लाख सड़क दुर्घटनाओं में डेढ़ लाख लोग मारे जाते हैं।
6. बिल में ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे प्रपत्रों को पूरी तरह आनलाइन कर पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है। इसमें पात्र आवेदकों को परेशान करने और समय पर सर्टिफिकेट न देने वाले अफसरों को दंडित करने की व्यवस्था भी की गई है।
7. प्रत्येक व्यक्ति को लाइसेंस प्रदाता अधिकारी के पास जाना पड़ेगा और यदि तीन दिन में लाइसेंस नहीं मिलता है तो आरटीओ के खिलाफ कार्रवाई होगी। लर्नर लाइसेंस घर बैठे आनलाइन मिलेगा।

उन्नत भारत अभियान

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं युक्त सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को 'उन्नत भारत अभियान' (Unnat Bharat Abhiyan) के अंतर्गत लाने पर अपनी सहमति व्यक्त की है।

क्या है

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

1. उक्त विषय के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के मध्य 12 जनवरी 2017 को एक समझौता हुआ था जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की विकासात्मक योजनाओं के निर्माण और वितरण में महत्त्वपूर्ण सुधार करना है।
2. यह परिकल्पित है कि इस अभियान के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि स्थानीय निकायों और कुछ चुनिन्दा ग्रामीण समुदायों से प्रत्यक्ष रूप से परिचित हो सकेंगे तथा उन्हें ग्राम पंचायतों के विकास योजनाओं से संबंधित आवश्यक जानकारी भी प्राप्त होगी।
3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस योजना का मसौदा तैयार किया गया है। इतना ही नहीं देश के कई भागों में इसके प्रथम चरण को लागू भी किया जा चुका है।
4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों तथा नियामकीय निकायों द्वारा स्वीकृत सभी सस्थानों को पिछड़े ग्राम पंचायतों एवं गाँवों को अपने संज्ञान में लेने तथा उनके ज्ञान और विशेषज्ञता का प्रयोग ग्राम पंचायतों के अवसंरचनात्मक ढाँचे में सुधार करने का सुझाव दिया है।
5. ध्यातव्य है कि इन सभी संस्थाओं को चुनी हुई पंचायतों के साथ सहयोग बढ़ाने तथा ग्रामीण विकास और पंचायती राज के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।

तीन प्रमुख मंत्रालयों की भूमिका

1. इस अभियान के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय को यह देखने का कार्य सौंपा गया है कि चुने हुए उच्च शिक्षण संस्थान जिला मजिस्ट्रेटों के परामर्श से पंचायतों को अपनाए और अपने ज्ञान का उपयोग ग्रामीण समुदायों के द्वारा सामना की जाने वाली बुनियादी जरूरतों और आजीविका अवसर के समाधान हेतु उचित रूप में करें।
2. त्रिपक्षीय समझौते के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्य ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी में जिला कलेक्टरों, डी.आर.डी.ए. और अन्य प्राधिकरणों की प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा देना है।
3. पंचायती राज मंत्रालय का कार्य जी.पी.डी.पी. (Gram Panchayat Development Plan) प्रक्रिया में ज्ञानवर्द्धक संस्थाओं की भागीदारी से संबंधित सुझाव सभी राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को जारी करना है ताकि वे चुनिन्दा समूहों की गुणवत्तापूर्ण जी.पी.डी.पी. तैयारी के हित में संगठनों के मध्य समन्वय स्थापित कर सके।
4. इसके अतिरिक्त कुछ निजी शिक्षण संस्थाओं और डीम्ड विश्वविद्यालयों को भी इस कार्यक्रम के

6. उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम को अगले दो वर्षों में लागू किया जाएगा। वर्तमान में देश के सभी जिलों को कवर करने के लिये कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

उदय में शामिल होने वाला 27 वां राज्य

उज्जवल डिस्कॉकम अशुरेन्स योजना (यूडीएवाई) के तहत भारत सरकार और मिजोरम सरकार के बीच राज्यर के बिजली वितरण विभाग के परिचालन में सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताकक्षर किए गए हैं। मिजोरम के इस समझौता ज्ञापन के हस्तालक्षर करने के साथ ही इस योजना में शामिल होने वाले राज्योंक / केन्द्र शासित प्रदेशों की संख्या अब 27 हो गई है।

क्या है

1. इस बदलाव की अवधि में सस्ता कोष, एटी एवं सी तथा पारेषण लॉस में कमी, ऊर्जा दक्षता में हस्तक्षेप आदि के माध्यसम से उदय में शामिल होने से मिजोरम को करीब 198 करोड़ रुपए का कुल शुद्ध लाभ होगा।
2. यह समझौता ज्ञापन राज्यि के बिजली वितरण विभाग के परिचालन की दक्षता में आवश्यबक वितरण ट्रांसफॉर्मर मीटरिंग, उपभोक्ता सूचकांक और लॉस की जीआईएस मैपिंग, ट्रांसफॉर्मरों के बदलाव और इनमें सुधार, अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटरिंग, फीडर ऑडिट आदि, एटी एवं सी लॉस और पारेषण लॉस में कमी के अलावा आपूर्ति लागत और समायोजन के बीच की खाई के समापन के माध्यवम से सुधार लाएगा।
3. इस अवधि के दौरान एटी एवं सी लॉस और पारेषण लॉस में क्रमश: 15 और 2.5 प्रतिशत तक कमी से करीब 166 करोड़ रुपए का अतिरक्ति राजस्वे मिल सकता है।

HIV एड्स पर नया कानून

अब HIV और एड्स से पीड़ित रोगियों को अपना इलाज करवाने, नौकरी पाने और शिक्षण संस्थानों में ऐडमिशन पाने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी और उन्हें भी आम लोगों की तरह बराबरी का हक हासिल होगा। साथ ही उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव दंडनीय अपराध होगा। लोकसभा में इस संबंध में एक बिल पास हुआ। HIV और एड्स

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

(बचाव और नियंत्रण) बिल के लोकसभा से पारित होने को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि उनकी सरकार HIV के पेशंट्स के मुफ्त इलाज के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा ने इस बिल को 21 मार्च को ही पास कर दिया था।

क्या है

1. स्वास्थ्य मंत्री ने साथ ही स्पष्ट किया कि HIV मरीजों के इलाज के लिए आधार नंबर जरूरी नहीं होगा और केवल ऐंटी रेट्रोवायरल सेंटर (ART) में पंजीकरण कराना होगा।
2. इस बिल के जरिए HIV एड्स पीड़ितों के संपत्ति अधिकारों, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के साथ ही उनके साथ सामाजिक भेदभाव को दंडनीय अपराध का दर्जा प्रदान किया गया है।
3. सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों में टीबी, HIV और मलेरिया के नियंत्रण में देश ने सफलता पायी है और अब HIV के मामलों में 67 प्रतिशत की कमी आयी है। ऐसे मामले 2.5 लाख से कम होकर 80 हजार पर आ गए हैं। इसी प्रकार HIV से होने वाली मौतों में भी 54 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है जो विश्व औसत से आगे है।
4. पहले सीडीएफ काउंट 500 पहुंचने पर ऐंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट एआरटी (ART) शुरू किया जाता था। उसके बाद सीडीएफ काउंट को 350 किया गया लेकिन सत्र के तुरंत बाद इसमें जांच और उपचार की नीति शुरू की जाएगी।
5. इसमें सीडीएफ काउंट के बजाय जिस दिन कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव पाया जाएगा, उसी दिन से उसका इलाज शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कई बार इस बात को दोहराया कि सरकार HIV मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और यह उपचार सौ फीसदी केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होगा।
6. पिछले साल सरकार ने ART ड्रग्स के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया था जो अब तक सर्वाधिक है। मंत्री ने साथ ही बताया कि HIV एड्स की जांच के लिए केंद्र सरकार 22 हजार परीक्षण सुविधा केंद्र भी खोलेगी। इससे पूर्व नड्डा ने सदन में बिल को चर्चा के लिए पेश करते हुए बताया कि इस विधेयक में इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं कि HIV एड्स पीडितों के साथ किसी भी प्रकार का उपचार संबंधी भेदभाव, सामाजिक भेदभाव और उनके खिलाफ दुर्भावना फैलाना दंडनीय अपराध होगा।
7. इस विधेयक में HIV एड्स पीड़ितों और उनके बच्चों का संपत्ति में हक कानूनी अधिकार के जरिए सुरक्षित करने के प्रावधान किए गए हैं। पीड़ितों के अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में विधेयक में एक लोकपाल की व्यवस्था की गयी है जहां शिकायत करने पर 30 दिन के भीतर कार्रवाई करनी होगी और इसका अनुपालन नहीं करने पर 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान होगा।
8. विधेयक में इस बात के भी प्रावधान किए गए हैं कि अदालती कार्यवाही, चिकित्सीय उपचार और सरकारी रिकॉर्ड में पीड़ित मरीजों के बारे में गोपनीयता बरती जाएगी और उनके संबंध में जानकारी को सार्वजनिक करना अपराध होगा।
9. इस विधेयक के संबंध में स्थायी समिति की 11 सिफारिशों में से 10 को स्वीकार कर लिया गया है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

गंगा अधिनियम के प्रारूप पर मालवीय समिति ने प्रस्तुत की रिपोर्ट

गंगा अधिनियम का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित मालवीय समिति ने नई दिल्लीर में अपनी रिपोर्ट केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री सुश्री उमा भारती को सौंपी। रिपोर्ट स्वीलकार करते हुए सुश्री भारती ने इसे एक 'ऐतिहासिक क्षण' करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सभी संबंधित पक्षों से इस पर व्याभपक विचार विमर्श के बाद इसे शीघ्र ही कानून का रूप देगी। सुश्री भारती ने अपने मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया कि वे इस रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन करने के लिए तत्काल एक उच्चर स्तोरीय समिति का गठन करें और यह समिति जल्द से जल्दर अपनी रिपोर्ट दें।

क्या है

1. समिति के अध्यअक्ष न्यायमूर्ति श्री गिरिधर मालवीय (सेवानिवृत्त) ने कहा कि यह एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी जिसे समिति के सदस्यों ने बखूबी निभाया। उन्होंने कहा कि इस कार्य में उन्हें केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का भरपूर सहयोग मिला।
2. समिति ने अपनी रिपोर्ट में गंगा की निर्मलता एवं अविरलता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं।
3. रिपोर्ट में गंगा के संसाधनों का उपयोग करने के बारे में जिम्मेदारी एवं जवाबदेही तय करने के बारे में कई कड़े प्रावधानों का उल्लेख है। समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पास पूर्व में उपलब्ध कानूनी प्रारूपों का भी अध्ययन किया।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

4. केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने प्रस्तावित गंगा अधिनियम का प्रारूप तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गत वर्ष जुलाई में इस समिति का गठन किया था।
5. समिति के अन्य् सदस्यि थेख्र श्री वी के भसीन, पूर्व सचिव विधायी विभाग भारत सरकार, प्रोफेसर ए के गोसाई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाान दिल्ली और प्रोफेसर नयन शर्मा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाान रूड़की। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के निदेशक श्री संदीप समिति के सदस्या सचिव थे।
6. 79 वर्षीय श्री गिरिधर मालवीय लंबे समय से गंगा संरक्षण अभियान से जुड़े रहे हैं और गंगा से उनका भावनात्मक लगाव है। वे गंगा महासभा के अध्य क्ष भी हैं।
7. महासभा की स्थापना उनके पितामह और काशी हिंदू विश्वभविद्यालय के संस्थाडपक और जाने माने स्वातत्रंता सेनानी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने ही की थी।

'नोमैडिक एलीफेंट-2017' शुरू

भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए 12वां संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 'नोमैडिक एलीफेंट-2017' 5 अप्रैल 2017 को शुरू हुआ। 14 दिवसीय इस सैन्य अभ्यास का आयोजन सेना के पूर्वी कमान अंतर्गत मिजोरम के वैरेंगते में किया जा रहा है।

क्या है

1. मंगोलियाई सेना की ओर से इस अभ्यास में कुल 45 सैन्यकर्मी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें नौ अधिकारी व 36 जवान शामिल हैं। वहीं भारतीय सेना की ओर से जम्मू कश्मीर राइफल्स बटालियन के तीन अधिकारी, चार जेसीओ व 39 जवान इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं।
2. इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकी माहौल से मुकाबले के लिए दोनों देशों की सेना के बीच तालमेल बढ़ाना है। इस तरह के संयुक्त अभ्यास से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों में वृद्धि होगी।

विदेशियों के लिए भी आधार कार्ड

सरकार ने कहा कि भारत में रहकर नौकरी या व्यापार करने वाले ऐसे विदेशियों के लिए भी आधार कार्ड जरूरी होगा, जो 182 दिनों से अधिक समय से यहां रह रहे हों और भारत में इनकम टैक्स भरते हैं। सेंट्रल बोर्ड और डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने स्टेटमेंट जारी कर यह बात कही है।

क्या है

1. सीबीडीटी ने साफ किया है कि जो प्रवासी 12 महीनों में 182 दिन या इससे अधिक दिनों से भारत में रह रहे हैं और यहां टैक्स चुका रहे हैं उन्हें आधार कार्ड के लिए आवेदन जरूरी है। अभी तक बहुत से प्रवासी यह उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें आधार से छूट मिल सकती है।
2. आधिकारिक बयान में कहा गया है, 'यह स्पष्ट किया जाता है कि आधार या नामांकन आईडी का ब्योरा उन लोगों को देना होगा जो आधार नंबर पाने के पात्र हैं। आयकर कानून की धारा 139 एए के तहत आधार नंबर देना उन लोगों के लिए अनिवार्य नहीं होगा जो आधार कानून, 2016 के मुताबिक निवासी नहीं हैं।
3. कानून के तहत निवासी से तात्पर्य उन लोगों से है जो नामांकन के लिए आवेदन करने की तारीख से पहले कम से कम 12 महीने या कुल 182 दिन तक भारत में रहे हैं।
4. आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी की लक्षित आपूर्ति, लाभ और सेवा) कानून, 2016 के तहत सिर्फ निवासी को ही आधार नंबर प्राप्त करने का अधिकार है।

शिक्षा का अधिकार कानून में संशोधन विधेयक पेश

केंद्र सरकार ने लोकसभा में शिक्षा का अधिनियम में आवश्यक संशोधन के लिए विधेयक पेश कर दिया है । यह विधेयक प्राथमिक शिक्षकों को अनिवार्य न्यूनतम योग्यता हासिल करने के लिए 2019 तक का समय देने के लिए लाया गया है। एक अप्रैल 2010 से लागू मौजूदा कानून के तहत शिक्षकों के लिए 31 मार्च 2015 से पांच वर्षो के भीतर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल करना अनिवार्य है।

क्या है

1. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 'बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) का अधिकार विधेयक 2017' पेश किया।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

2. विधेयक के विषय की व्याख्या और कारण में इसे स्पष्ट किया गया है। कहा गया है कि राज्य सरकारों ने अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए समय बढ़ाने का आग्रह किया है। समय बढ़ाने से प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।
3. मंत्रालय ने अधिनियम में एक नया प्रावधान जोड़ा है। इसके तहत छह से 14 वर्ष तक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने की व्यवस्था है।
4. नए प्रावधान के तहत 31 मार्च 2015 नियुक्त या नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल हर शिक्षक जिनके पास न्यूनतम योग्यता नहीं है वह 2019 तक न्यूनतम योग्यता हासिल कर सकेंगे ।
5. ऐसे शिक्षकों को प्रस्तावित कानून लागू होने की तारीख से चार वर्ष के भीतर योग्यता हासिल करनी होगी। प्रशिक्षण पर खर्च सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत आवंटन से होगा। दरअसल तमाम राज्य सरकारें सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण जारी रखने में समर्थ नहीं हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है।

सर्वे ऑफ इंडिया के मानचित्रों लिये आधार की अनिवार्यता

सर्वे ऑफ इंडिया (Survey of India) देश का सबसे प्राचीन वैज्ञानिक संगठन और मानचित्रों का आधिकारिक निर्माणकर्ता है। धातव्य है कि कुछ समय पहले ही एस.ओ.आई. द्वारा नक्शे (Nakshe) नामक एक वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है जिसके कारण इसके सभी 7,000 मानचित्रों में से 3,000 को फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। परन्तु, इस सब में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सभी मानचित्रों को डाउनलोड करने के लिये व्यक्ति को अपनी आधार संख्या को इससे संबद्ध करना होगा।

क्या है

1. सर्वे ऑफ इंडिया के मानचित्रों को रक्षा और नागरिक उद्देश्यों के संदर्भ में तैयार किया जाता है।
2. इन्हें देश के आकार, विस्तार और भौगोलिक गुणों के मानक संदर्भ में तैयार किया जाता है।
3. नक्शे पोर्टल का तात्पर्य यह है, 'सुरक्षा के प्रति चिंता और आधार युक्त उपयोगकर्ता के प्रमाणीकरण और उपयोगकर्ता की आधार संख्या के माध्यम से उन्हें ट्रैक करना है''।
4. गौरतलब है कि एसओआई द्वारा प्रदत्त ये सभी मानचित्र 'नक्शे' नामक पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराए गए है।
5. इससे न केवल देश के नीति निर्माताओं को देश की वास्तविक स्थिति के विषय में सटीक जानकारी प्राप्त होगी बल्कि इसके माध्यम से गाँव के निवासियों और पंचायतों के लिये भी सटीक सूचना प्राप्त करना पहले की अपेक्षाकृत अधिक आसान हो जाएगा।
6. वर्तमान में, कई प्रकार के संगठनों, संस्थाओं और लोगों को विशिष्ट प्रकार के मानचित्रों की आवश्यकता होती हैद्य कई बार तो स्वयं मंत्रालयों को निश्चित नक्शों को प्राप्त करने के लिये भुगतान तक करना पड़ता है।
7. जबकि अब देश के सभी नागरिकों को ये सभी नक्शे बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका कारण यह है कि इन के निर्माण कार्य में सरकार पहले ही भुगतान कर चुकी है।

निमकेयर विश्व स्वास्थ सम्मेलन 2017 का उद्घाटन

राष्टप्रति श्री प्रणब मुखर्जी ने 7 अप्रैल, 2017 नई दिल्ली में पहले निमकेयर (एनआईएमसीएआरई) विश्व स्वारस्यष सम्मेयलन 2017 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर निमकेयर ने इस सम्मेलन के आयोजन के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है। प्रथम निमकेयर विश्व स्वास्थ्य दिवस सम्मेलन का मूल-वाक्य 'मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक हों' है। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में पूरे विश्व में विकलांगता पैदा होती है। मनुष्य की उत्पादकता में किसी भी प्रकार का मानसिक विकार होने के कारण कमी आ जाती है तथा कार्यस्थलों में या परिवार में परिस्थितियां प्रभावित हो जाती हैं।

क्या है

1. मानसिक स्वास्थ्य के विकार का दायरा बहुत विशाल है, जिसमें साधारण से लेकर जटिल समस्याएं शामिल हैं। अक्ससर देखा गया है कि अगर साधारण विकारों को समय रहते ठीक नहीं किया गया तो मरीज की हालत जटिल हो जाती है। इस तरह के मरीज परिवारों पर बोझ बन जाते हैं।
2. सभी प्रकार के मानसिक स्वोस्थो विकारों में संभवत: अवसाद बहुत आम है। अवसाद में सभी देशों के हर उम्र के त हो सकते हैं। निमहांस (एनआईएमएचएएनएस) द्वारा किये गये राष्ट्री य मानसिक स्वास्थ सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार भारत की 5.2 प्रतिशत व्यस्क आबादी किसी न किसी प्रकार के अवसाद से ग्रस्त् है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

3. अवसाद की समस्याकओं पर प्राय: ध्यान नहीं दिया जाता, क्यों कि परिवार के सदस्य इसे ठीक से समझ नहीं पाते। मानसिक विकार के साथ सामाजिक कलंक भी जुड़ जाता है, चाहे उसका आसान उपचार क्यों न उपलब्ध हो। भारत में यह बड़ी समस्या है। बहरहाल, लोग इस समस्यां के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं।
4. पारम्परिक मूल्यों वाली हमारी पारिवारिक प्रणाली मानसिक स्वास्थ विकारों को दूर करने में बहुत कारगर है। उन्होंने चिकित्सक समुदाय से आग्रह किया कि वे सामाजिक सहायता प्रणालियों, आध्यात्मिक विश्वासों और अभ्यासों पर ध्यान दें। इनके साथ लोगों को स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए योग प्रणाली का भी इस्तेमाल करें।
5. देश में मानसिक स्वास्थ प्रोफेशनलों की भारी कमी है और इस कमी को टेली-मेडीसन के जरिये प्रभावशाली तरीके से दूर किया जा सकता है।
6. मानसिक स्वास्थ सलाहकारों की आवश्यंकताओं के मद्देनजर ग्रामीण और शहरी आबादी के लिए ई-केप एंड एसओएल टेली-साईकियेट्री एप्लिकेशन की शुरूआत करके विश्व स्वास्थ्य दिवस सम्मेलन ने सही दिशा में काम उठाया है।

पहली बार चार बड़े हाई कोर्ट में महिलाएं हुईं मुख्य न्यायाधीश

पुरूष प्रधान वाली उच्च न्यायपालिका में अब महिलाओं की संख्या भी बढ़ रही है, जो अपने आप में एक शुभ संकेत है। देश में पहली बार चारों बड़े और पुराने उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर महिलाएं आसीन हुई हैं। इनमें बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली हाई कोर्ट शामिल है जहां चीफ जस्टिस महिलाएं हैं।

क्या है

1. 31 मार्च को जब इंदिरा बनर्जी को मद्रास हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया तो महिलाओं के नाम पर हाइकोर्ट्स में एक इतिहास दर्ज हो गया। इन चारों हाई कोर्ट की स्थापना औपनिवेशिक काल के दौरान हुई थी। मुख्य न्यायाधीश सहित मद्रास हाई कोर्ट में कुल 6 महिला न्यायाधीश (जज) हैं, जबकि पुरुष जजों की संख्या 53 हैं।
2. बॉम्बे हाई की बात करें तो वहां की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मंजूला चेल्लूर है। जस्टिस मंजूला ने पिछले साल 22 अगस्त को बॉम्बे हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया था।
3. जस्टिस मंजुला चेल्लूर के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में नंबर दो की पोजिशन पर भी एक महिला जस्टिस वी एम ताहिलरामनी काबिज हैं।
4. देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुकाबले सबसे ज्यादा महिला जजों की संख्या भी बॉम्बे हाइकोर्ट में है। यहां 11 महिलाएं जज हैं जबकि पुरूष जजों की संख्या 61 हैं।
5. दिल्ली हाइकोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश के पद पर जस्टिस जी रोहिणी काबिज हैं जिन्होंने 13 अप्रैल, 2014 को कार्यभार संभाला था। दिल्ली हाई कोर्ट में पुरुष जजों की संख्या 35 है, जबकि महिला जजों की संख्या 9 है। यहां भी नंबर दो की पोजिशन पर महिला जज जस्टिस गीता मित्तल पदासीन हैं।
6. निषिता निर्मल माहत्रे 1 दिसंबर, 2016 से कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद की जिम्मेदारी निभा रहीं हैं। लेकिन यहां पुरूष जजों की तुलना में (35) महिला जजों की संख्या (4) बेहद कम है।
7. पूरे देश की बात करे तो देशभर के 24 उच्च न्यायालयों में 632 जज हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या केवल 68 (10.7 फीसद) है।
8. 28 जजों वाले सुप्रीम कोर्ट में भी एकमात्र महिला जज के रूप में जस्टिस आर. भानुमति पदासीन हैं।

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खिलाफ याचिका रद

दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिका रद कर दी है। मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी जुलाई 2014 में इस मुद्दे पर याचिका रद कर चुका है। ऐसे में इस पर सुनवाई का कोई आधार नहीं है।

क्या है

1. याचिका विजयलक्ष्मी झा ने दायर की थी। उनका कहना था कि अनुच्छेद 370 के तहत अस्थायी रूप से जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान था।
2. इसका उद्देश्य वहां पर विधानसभा का गठन करना था। ऐसे में वर्ष 1957 में वहां विधानसभा के गठन के साथ ही अनुच्छेद के तहत किया गया प्रावधान स्वयं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन 65 वर्ष बीतने के बाद भी यह लागू है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

3. याचिका में इस तथ्य का उल्लेख भी किया गया कि 17 नवंबर 1956 और 26 जनवरी 1957 को जम्मू-कश्मीर के लिए एक अलग संविधान बना दिया गया।
4. राष्ट्रपति और संसद ने इसे अब तक मंजूरी नहीं दी है। ऐसे में अलग संविधान की कोई वैधता नहीं है। याची के अनुसार, उन्हें 28 मई 2014 को समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ था कि केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का निर्णय लिया है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में यह अब भी लागू है।

अंतर्राष्ट्रीय

आर्थिक तौर पर सार्क से अलग थलग हुआ पाक

आतंकवाद को मदद देने की वजह से पाकिस्तान पहले ही दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कूटनीतिक तौर पर अलग थलग हो चुका है लेकिन अब वह इस क्षेत्र से आर्थिक तौर पर भी अलग थलग होता जा रहा है। जब सार्क संगठन के भारत समेत छह प्रमुख देशों (बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव) के अलावा म्यांमार ने जब इस पूरे क्षेत्र की आर्थिक प्रगति का नया रोडमैप बनाया तो उसमें पाकिस्तान का कोई नाम नहीं था। इन देशों के वित्त मंत्रियों की हुई दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) की बैठक में म्यांमार को भी शामिल कर दिया लिया गया है। बैठक में इन वित्त मंत्रियों के बीच वर्ष 2025 तक सभी देशों के सकल घरेलू उत्पाद में 70 अरब डॉलर की वृद्धि करने और दो करोड़ लोगों को रोजगार दिलाने का रोडमैप तैयार किया गया है।

क्या है

1. सासेक के वित्त मंत्रियों की बैठक संबोधित करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 'भारत अपनी श्एक्ट ईस्ट नीति' को और धार देगा ताकि इन देशों के साथ हर तरह के संपर्क को बेहतर किया जा सके।
2. भारत की कोशिश होगी कि बांग्लादेश व म्यांमार के जरिए वह पूर्वी एशियाई देशों तक अपनी पहुंच बनाये। इससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में मदद मिलेगी।
3. सासेक की स्थापना 16 वर्ष पहले भारत ने बांग्लादेश, भूटान व नेपाल के साथ किया था। लेकिन पिछले वर्ष सार्क देशों की बैठक के टलने के बाद कूटनीतिक स्तर पर भारत ने इस संगठन के विस्तार की प्रक्रिया तेज कर दी है। यह पहला मौका है जब दक्षिण एशिया के सात देशों ने एक साझा आर्थिक भविष्य को लेकर श्विजन पत्रश जारी किया है।
4. विजन पत्र के मुताबिक सासेक के देशों के बीच हाइड्रोकार्बन व ऊर्जा के अन्य क्षेत्रों में करीबी सहयोग की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। सभी देशों के बीच साझा इकोनोमिक कोरिडोर भी विकसित किया जाएगा।
5. इसमें सासेक देशों के संगठन को दक्षिण एशिया को एक मजबूत आर्थिक संगठन बनाने की इच्छा जताई गई है।
6. सभी देशों ने अपने संबंधित मंत्रालयों व विभागों को आदेश दिया है कि किस तरह से आगे सहयोग को बढाया जाए इस पर अलग से मशविरा दे।
7. बेरोजगारी को इस पूरे क्षेत्र की एक अहम समस्या मानते हुए इसे दूर करने के लिए संयुक्त रणनीति बनाने की बात भी कही गई है।

भारत-बांग्लादेश के बीच हुए 22 अहम समझौतें

8 अप्रैल 2017 को दिन भर पीएम नरेंद्र मोदी व बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय बैठक और मंत्रिस्तरीय बैठकों का सार एक पंक्ति में यह है कि इन दोनों देशों के रिश्तों के बेहतरीन दिनों की अभी शुरुआत भर हुई है। दोनों प्रधानमंत्रियों के सामने रक्षा से लेकर परमाणु ऊर्जा तक और सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर न्यायायिक प्रक्रिया तक के क्षेत्र में 22 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये। पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को पीएम मोदी ने यह कह कर नया आयाम दे डाला कि वे, "भारत के साथ ही बांग्लादेश के विकास के भी सपने देखते हैं।"

क्या है

1. शेख हसीना सरकार की बहुत चाहत के बावजूद तीस्ता जल बंटवारे पर समझौता नहीं हो सका लेकिन पीएम मोदी ने यह वादा जरुर किया कि इस मुद्दे पर जल्द से जल्द वह सहमति बनाने की कोशिश करेंगे।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

2. शेख हसीना हर हालत में चाहेंगी कि इस पर मोदी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तैयार कर ले क्योंकि बांग्लादेश में अगले वर्ष चुनाव है और यह मुद्दा वहां राजनीतिक रंग ले सकता है। लेकिन हसीना के लिए अपने यहां बताने के लिए यह जरुर होगा कि भारत से उन्हें एकमुश्त 5 अरब डॉलर की वित्तीय मदद मिला है।
3. इसमें से 4.5 अरब डॉलर भारत बांग्लादेश में विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने में देगा। जबकि 50 करोड़ डॉलर की मदद भारत से जरुरी रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए दी जाएगी।
4. इससे पिछले तीन वर्षो में नई दिल्ली की तरफ से ढाका को दिए जाने वाले आर्थिक मदद का आकार आठ अरब डॉलर का हो जाएगा। लेकिन यह सुनिश्चित करेगा कि ढाका नई दिल्ली का का एक अहम रक्षा सहयोगी व बाजार बने।
5. भारत व बांग्लादेश के बीच 22 समझौतों में से तीन समझौते परमाणु क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो बताता है कि दोनों देश किस तरह से रिश्तों को नई राह दे रहे हैं।
6. इससे आने वाले दिनों में भारत बांग्लादेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने में भी मदद करेगा। यह पहली बार है कि भारत परमाणु तकनीकी का निर्यात करने की कोशिश कर रहा है। पीएम हसीना ने अपनी तरफ से भारत को पूरा आश्वासन दिया है कि उनके देश का इस्तेमाल अब भारत विरोधी के लिए नहीं होगा।
7. आतंकवाद पर उनकी सरकार की जीरो-टोलरेंस की नीति जारी रहेगी। भारत-बांग्लादेश सीमा पर शांति व सुरक्षा बनाये रखने के लिए वह हर मुमकिन कोशिश करेंगी।
8. मोदी ने भी हसीना सरकार की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों को हर किसी के लिए प्रेरणा का कारण बताया। दोनों देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ एक दूसरे की मदद करने को लेकर भी एक समझौता हुआ है।

एचआइवी एड्स के इलाज की दिशा बड़ी कामयाबी

एचआइवी एड्स के इलाज की दिशा में वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी मिली है। वैज्ञानिकों ने एचआइवी प्रतिरोधी कोशिकाओं का समूह तैयार करने का तरीका ईजाद किया है। ये कोशिकाएं तेजी से वायरस से प्रभावित कोशिकाओं का स्थान लेने में सक्षम होती हैं।

क्या है

1. अमेरिका स्थित द स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट (टीएसआरआइ) के शोधकर्ताओं ने एचआइवी से लड़ने वाले एंटीबॉडी को इम्यून कोशिकाओं के साथ जोड़कर इस काम को अंजाम दिया। शोधकर्ता जिया शी ने कहा, 'इस प्रक्रिया से मिलने वाली सुरक्षा लंबी अवधि तक कारगर रहेगी।'
2. एचआइवी के इलाज की वर्तमान तकनीक में एचआइवी से लड़ने वाले एंटीबॉडी खून में तैरते हुए वायरस से लड़ते हैं। नई तकनीक इस मामले में ज्यादा कारगर है।
3. इसमें एंटीबॉडी कोशिका की सतह से जुड़ जाते हैं और वायरस कोशिका को संक्रमित नहीं कर पाता। शी ने इस प्रक्रिया को नेबर इफेक्ट (पड़ोसी का प्रभाव) नाम दिया है। उन्होंने कहा कि सतह पर चिपका हुआ एक एंटीबॉडी खून में घूम रहे कई एंटीबॉडी से ज्यादा कारगर है।
4. एचआइवी के खिलाफ इस तकनीक को आजमाने से पहले वैज्ञानिकों ने सामान्य जुकाम की वजह बनने वाले राइनोवायरस पर भी इसे सफलतापूर्वक आजमाया था।

ब्रिटेन से चीन के लिए चली मालगाड़ी

ब्रिटेन से चीन के लिए पहली मालगाड़ी 10 अप्रैल 2017 को रवाना हुई। 30 बोगियों वाली 600 मीटर लंबी इस मालवाहक ट्रेन में व्हिस्की, सॉफ्ट ड्रिंक्स, विटामिंस और बेबी प्रोडक्ट्स आदि लदे हैं। पूर्वी इंग्लैंड से पूर्वी चीन के लिए रवाना हुई यह ट्रेन 12 हजार किलोमीटर का सफर तय करेगी और सात देशों से गुजरेगी। यह 18 दिन में चीन पहुंचेगी। आम तौर पर समुद्री जहाज से इतनी दूरी तय करने में इसका दुगुना वक्त लगता है।

क्या है

1. चीन से ब्रिटेन के लिए पहली मालगाड़ी 18 जनवरी को पहुंची थी जिसमें डे और अन्य रिटेल सामान था। ट्रेन पूर्वी लंदन में एसेक्स फॉर बार्किंग में स्टैनफोर्ड-ले-होप से रवाना हुई। यहां से यह फ्रांस में चौनल टनल से गुजरेगी। फिर बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, रूस और कजाकिस्तान होते हुए चीन में यिवु 27 अप्रैल को पहुंचेगी।
2. यह रेल सेवा चीन के 'वन बेल्ट, वन रोड' कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसके तहत चीन को पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले लगभग 2,000 साल पुराने सिल्क रोड ट्रेडिंग रूट को नए सिरे से शुरू किया जाने की योजना है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

3. पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा था कि पश्चिमी देशों की तरफ बढ़ने के लिए चीन को ब्रिटेन को अनिवार्य गंतव्य के रूप में लेना होगा। उनका कहना था कि इसके लिए चीनी मुद्रा युआन के निवेश के लिए लंदन सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग सेंटर बन जाना चाहिए।
4. अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे का कहना है कि चीन के साथ ब्रिटेन के संबंध सुनहरे काफी अच्छे हैं। वह चाहती हैं कि यूरोपीय संघ से अलग हो जाने के बाद चीन की ओर से अरबों डॉलर का निवेश ब्रिटेन में हो।
5. गौरतलब है कि ब्रिटेन को दो साल के भीतर यूरोपीय संघ से अलग होना है और वह दुनिया के बाकी देशों से अपने व्यापार संबंध मजबूत करने की कोशिश में लगा है।

समुद्र के अंदर चला 35 मिनट का सम्मेलन

10 अप्रैल 2017 को कोवलम में ग्रोव बीच के अंदर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पांच कंपनियों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। हेमा मेनन यूएसटी ग्लोबल की केंद्र प्रमुख, दिनेश पी थाम्पी उपाध्यक्ष टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एवन मॉबिलिटी सॉल्यूशंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रनी थॉमस जाचिर्या, श्याम कुमार कंटेंट मैनेजर न्यूलिक्स और राजगोपाल अय्यर यूडीएस ग्रुप ऑफ होटल के सीईओ यहां बतौर प्रतिभागी रहे।

क्या है

1. यह सम्मेलन बॉन्ड सफारी और उदय समुद्र होटल द्वारा आयोजित किया गया था। इसका शीर्षक 'महासागर प्रेम' था, जिसका उद्देश्य समुद्री जीवन की रक्षा के लिए दीर्घकालिक योजना का प्रारूप तैयार करना है।
2. बॉन्ड सफारी के प्रबंध निदेशक जैक्सन पीटर ने कहा, बहुत से लोग इस बात से अंजान होंगे कि महासागर प्रोटीन का विश्व का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके साथ ही उन्होंने बताया, 'करीब 9 मिलियन टन प्लास्टिक अक्सर समुद्र में डाल दिया जाता है।'
3. प्रतिभागियों ने करीब 35 मिनट समुंद्र में अंदर बिताया और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा का समर्थन किया। टीसीएस के दिनेश पी थाम्पी ने कहा, 'यह हम सब का दायित्व है कि समुद्र को गंदा होने से बचाए।'

अफगानिस्तान में सबसे बड़े बम से मरे गिराया गया

अफगानिस्तान में आइएस के ठिकाने पर सबसे बड़ा गैर परमाणविक बम गिराने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार ने सेना को कार्रवाई के लिए पूरे अधिकार दे रखे हैं, इसलिए यह सफल कार्रवाई संभव हो पाई। 13 अप्रैल 2017 रात हुई इस कार्रवाई में सुरंग में बना आइएस का ठिकाना तबाह हो गया और उसमें मौजूद 36 आतंकी मारे गए।

क्या है

1. पाकिस्तान सीमा के नजदीक नांगरहार प्रांत के अचिन जिले में स्थित आइएस (खोरसान) के ठिकाने पर अमेरिकी सेना ने 21,600 पाउंड का जीपीएस गाइडेड मैसिव ऑर्डनेंस एयर ब्लास्ट बम (एमओएबी) गिराया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता एडम स्टंप के मुताबिक इस बम का पहली बार किसी लड़ाई में इस्तेमाल किया गया।
2. यह अमेरिका का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणविक बम है। इसकी शक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हाल ही में सीरिया के शायरात एयरबेस पर जिन टॉमहॉक मिसाइलों से अमेरिका ने तबाही मचाई थी, उनके वारहेड में महज एक हजार पाउंड का बम लगा था। सबसे बड़े बम को एमसी-130 विमान से गिराया गया और पूरी कार्रवाई को एयरफोर्स की स्पेशल ऑपरेशंस कमांड ने अंजाम दिया।
3. राष्ट्रपति ट्रंप ने सेना की इस कार्रवाई को बहुत सफल करार दिया। कहा कि यह अमेरिका के लिए एक और सफलता वाला मुकाम है। इसके लिए हमें हमारी सेना पर गर्व है। हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, जिसे हम पूरी क्षमता से कार्रवाई करने का पूरा अधिकार देते हैं।

ई-वीजा शक्ति का विस्तार

1 अप्रैल, 2017 से देश में एक नई उदारवादी ई-वीजा व्यवस्था लागू हो गई है। यह दुनिया भर में भारत की यात्रा की योजना बना रहे 161 देशों के नागरिकों के लिये यह एक खुशी का अवसर है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के उपरांत अब ऑनलाइन आवेदन करने की निर्धारित अवधि तथा भारत में रहने की अवधि दोनों को एक साथ बढ़ा दिया गया है। हालाँकि, यहाँ एक ओर बात के विषय में गौर करने की आवश्यकता है कि भारतीय राजनयिक मिशनों द्वारा वीजा प्रदान करने की परंपरागत प्रक्रिया को भी बंद नहीं किया जाएगा।

क्या है

1. ई-वीजा की प्रणाली का विचार बहुत पुराना नहीं हैद्य बल्कि पिछले सात वर्षों से ही यह व्यवस्था चलन में आई है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

2. वर्ष 2010 में ही भारत ने पाँच देशों - जापान, सिंगापुर, फिनलैंड, लक्समबर्ग और न्यूजीलैंड के नागरिकों के लिये ही आगमन पर पर्यटक वीजा (Tourist Visa on Arrival -TVOA) की शुरूआत की थी।
3. इसके एक साल बाद ही भारत सरकार ने कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार और इंडोनेशिया के नागरिकों के लिये भी इस योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया।
4. इसके पश्चात् वर्ष 2014 में केंद्र में सरकार के बदलने के बाद इस प्रणाली को काफी बढ़ावा मिला।
5. भारत की यात्रा को और अधिक सहज अनुभव बनाने के लिये इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकार (Electronic Travel Authorization-ETA) से युक्तब आगमन पर पर्यटक वीजा (TVOA) की सुविधा 27 सितंबर, 2014 से शुरू कर दी गई।
6. टी.वी.ओ.ए-ई.टी.ए. के अंतर्गत 9 नामित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के माध्यम से भारत में प्रवेश के लिये 43 देशों के नागरिकों को ऑनलाइन पूर्व प्राधिकार (pre-authorization) प्राप्त था। विदित हो कि यह एक एकल प्रवेश वीजा है, जो 30 दिनों के लिए वैध होगा।

अन्य महत्त्वपूर्ण पक्ष

1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यापार को आसान बनाने, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने तथा विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि करने के लिहाज से 30 नवंबर, 2016 को वीजा व्य वस्थान को पहले की अपेक्षा अधिक उदार, सरल और तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया।
2. इसे नई वीजा व्यवस्था को अभी हाल ही में 1 अप्रैल से लागू किया गया है। अब ई-वीजा में पर्यटक, व्यापार, चिकित्सा, रोजगार, इंटर्न वीजा और फिल्म वीजा जैसी कई नई श्रेणियों को भी स्थान दिया गया हैं।
3. विभिन्न देशों के क्रूज पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिये अब ई-वीजा सुविधा 24 हवाई अड्डों के साथ-साथ 3 बंदरगाहों (कोचीन, गोवा और मैंगलोर) के माध्यम से भारत में प्रवेश के लिये 161 देशों के नागरिकों के लिये उपलब्ध कराई जा रही है।
4. ई-वीजा योजना के तहत आवेदन की अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है। ताकि पर्यटक अपनी यात्रा की योजना को बेहतर ढंग से तैयार कर सकें।
5. ई-पर्यटक, ई-व्यारपार वीजा पर दोहरे प्रवेश तथा ई-चिकित्सा वीजा पर तिहरे प्रवेश के साथ भारत में रूकने की अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिनों तक कर दिया गया है।
6. चिकित्सा के लिये बड़ी संख्यार में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे कुछ भारतीय हवाई अड्डों पर पहुंचने वाले पर्यटकों के लिये अलग से आव्रजन काउंटर और सुविधा डेस्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

आर्थिक

वित्त विधेयक को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी

वित्त विधेयक 2017 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही यह प्रभावी हो गया। दो लाख रुपये से अधिक नकदी लेनदेन पर रोक और टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार अनिवार्य बनाने जैसे विधेयक के प्रावधान लागू हो गए हैं।

क्या है

1. वित्त विधेयक 2017 के सभी कर और अन्य प्रस्ताव प्रभावी हो गए। ऐसा पहली बार हुआ है जब वार्षिक बजट के साथ कर प्रस्ताव वित्त वर्ष के पहले ही दिन से प्रभावी हुए हैं। औपनिवेशिक कालीन परंपरा को तोड़ते हुए इस साल पहली बार फरवरी के अंत की जगह एक फरवरी को बजट पेश किया गया।
2. इस वजह से वित्त विधेयक 2017 के बजट और कर प्रस्तावों पर अनुदान या खर्च की मांग की मंजूरी की विधायी प्रक्रिया 30 मार्च तक पूरी हो गई। इसके अगले दिन इस पर राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई। इससे सरकार को कल्याणकारी कार्यक्रमों और कर योजनाओं को लागू करने के लिए अधिक समय मिल जाएगा।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

3. पहले फरवरी के अंत में बजट पेश किया जाता था। इस कारण संसद से मंजूरी की प्रक्रिया मई के मध्य में पूरी होती थी। इसके कुछ हफ्ते बाद ही मानसून की शुरुआत हो जाती थी। ऐसे में सरकारी विभागों का खर्च मानसून बाद अगस्त के अंत या सितंबर में शुरू हो पाता था।
4. बजट की तारीख पहले करने के अलावा इस बार बजट में योजना और गैर योजना के भेद को भी खत्म कर दिया गया। साथ ही करीब एक सदी की व्यवस्था को खत्म कर रेल बजट को भी आम बजट में मिला दिया गया।

संसद का बजट सत्र समाप्त

संसदीय कार्य और रसायन तथा उर्वरक मंत्री श्री अनंत कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि संसद का बजट सत्र 2017 अनेक दृष्टि से एतिहासिक रहा। श्री अनंत कुमार ने बताया कि संसद का बजट सत्र मंगलवार 31 जनवरी, 2017 को आरंभ हुआ था। इसे 12 अप्रैल, 2017 को अनिश्चिक काल के लिए स्थगित किया गया।

बजट सत्र 2017 को तीन प्रमुख दृष्टि से एतिहासिक उपलब्धि

1. केंद्रीय बजट का पहले प्रस्तुतीकरण और 31 मार्च तक नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पहले सरकार के सभी वित्तीय कामकाज पूरे किए गए।
2. वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के सभी सहायक अधिनियमों को पारित करना।
3. एकीकृत बजट प्रस्तुत और पारित करना।

क्या है

1. तीन महत्वपूर्ण विधेयक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान (संशोधन) विधेयक 2017, मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2017, फैक्ट्री (संशोधन) विधेयक 2016 दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं हो सके।
2. बजट सत्र 2017 के दौरान संपन्न विधायी कार्यों के बारे में बताया गया की बजट सत्र के पहलेभाग में लोक सभा के 7 और राज्य सभा की 8 बैठकें हुई।
3. सत्र के दूसरे हिस्से में लोकसभा की 22 और राज्यसभा की 21 बैठकें हुई। पूरे सत्र के दौरान लोक सभा और राज्य सभा की 29-29 बैठकें हुई। लोकसभा में 113.27 प्रतिशत और राज्य सभा में 92.43 प्रतिशत कार्य हुए।
4. वर्ष का पहला सत्र होने के कारण राष्ट्रपति ने 31 जनवरी, 2017 को संविधान के अनुच्छेद 87 (1) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया और संसद सत्र आहुत करने के बारे में बताया।
5. 9 फरवरी, 2017 को दोनों सदनों की बैठक छुट्टी के लिए 27 दिनों के लिए स्थगित की गई। और दोनों सदनो की बैठक फिर 9 मार्च, 2017 को हुई ताकि विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर संबंधित स्थायी समितियां विचार कर सकें।
6. वर्ष 2016-17 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों और रेलवे से संबंधित वर्ष 2013-14 के लिए अतिरिक्तअ अनुदान मांगों पर भी लोकसभा में संबंधित विनियोग विधेयकों के साथ मतदान हुआ, जिन्हें बाद में राज्यसभा द्वारा वापस कर दिया गया। इस अवधि के दौरान केन्द्री य बजट पर आम परिचर्चा पूरी हुई और इसके साथ ही राज्या सभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चाएं हुई।
7. इस सत्र के दौरान अन्य बातों के अलावा एक खास बात यह रहीं कि चार ऐतिहासिक विधेयकों यथा, केन्द्री य वस्तुी एवं सेवा कर विधेयक 2017, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017, वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) विधेयक 2017 और केन्द्र शासित प्रदेश वस्तुं एवं सेवा कर विधेयक 2017 को दोनों ही सदनों ने पारित कर दिया, जिससे देश भर में 01 जुलाई, 2017 से वस्तुत एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने का मार्ग प्रशस्तध हो गया।
8. इस सत्र के दौरान कुल मिलाकर 24 विधेयक (लोकसभा में 24) पेश किये गये। लोकसभा में 23 विधेयक पारित हुए और राज्यक सभा में 14 विधेयक पारित हुए।
9. सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में कुल मिलाकर 18 विधेयक पारित हुए। लोकसभा में पेश किये गये विधेयकों, लोकसभा द्वारा पारित किये गये विधेयकों, राज्यि सभा द्वारा पारित किये गये विधेयकों, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किये गये विधेयकों और वापस लिये गये विधेयक की सूची अनुलग्नसक में दी गई है।
10. सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कुछ महत्व पूर्ण विधेयकों जैसे कि पारिश्रमिक का भुगतान (संशोधन) विधेयक 2017, मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक 2017, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक 2017 और कर्मचारी क्षतिपूर्ति (संशोधन) विधेयक 2017 को भी इस सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया। शत्रु सम्पत्ति (संशोधन एवं वैधता) विधेयक 2017 को भी संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

11. लोकसभा में नियम 193 के तहत सतत विकास के लक्ष्यों पर अल्पकालिक चर्चा हुई, जो अपूर्ण रही। राज्यख सभा में नियम 176 के तहत इन दो विषयों पर अल्पसकालिक चर्चा हुई : 1. चुनाव सुधार 2. आधार- इसका क्रियान्वयन एवं इसके निहितार्थ।
12. राजस्व सभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाया गया, जो विशेष श्रेणी के दर्जे की अवधारणा जारी रखने की जरूरत पर विचार-विमर्श के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक आयोजित करने की आवश्यकता से संबंधित था।

GST संशोधनों को मंजूरी

बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक जुलाई 2017 से लागू करने का रास्ता साफ करते हुए राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने जीएसटी के लिए जरूरी चार विधेयकों को मंजूरी दे दी है। हाल ही में संसद ने इन विधेयकों को पारित किया था। अब राज्य विधानसभाएं एसजीएसटी विधेयक को मंजूरी देंगी जिसके बाद जीएसटी लागू करने के लिए जरूरी विधायी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

क्या है

1. राष्ट्रपति ने जिन विधेयकों को मंजूरी दी है उनके नाम हैं- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) विधेयक 2017, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आइजीएसटी) विधेयक 2017, वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) विधेयक, 2017 और संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, 2017। इन विधेयकों को लोक सभा ने 29 मार्च तथा राज्य सभा ने 6 अप्रैल को पारित किया था।
2. जीएसटी पर चर्चा बीते एक दशक से चल रही थी लेकिन अब यह मूर्तरूप लेने के करीब पहुंचा है। जीएसटी लागू होने पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर तथा वैट जैसे कई परोक्ष कर समाप्त हो जाएंगे।
3. जीएसटी विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब राज्यों की विधान सभाएं एसजीएसटी विधेयक को मंजूरी देंगी। वहीं जम्मू कश्मीर को अपने यहां एसजीएसटी की तरह का ही अलग कानून बनाना होगा। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर यह कानून बनाएगा जो देश के बाकी राज्यों के जीएसटी कानून के समान ही होगा।
4. दरअसल एसजीएसटी विधेयक में राज्य जीएसटी लागू करने संबंधी प्रावधान हैं। इसलिए इसके पारित होने के बाद जीएसटी के लिए जरूरी विधायी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
5. इस बीच जीएसटी काउंसिल ने 18 और 19 मई को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में वस्तु और सेवावार जीएसटी की दरों को अंतिम रूप देगी। फिलहाल अधिकारियों की समिति जीएसटी की दरें तय करने में जुटी है।

शेल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई

हाल ही में 500 शेल (खोखा) कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंजीनियरिंग के एक छात्र समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों व्यक्तियों में से एक जीडी रेड्डी को बेंगलुरु से और दूसरे के. लियाकत अली को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी मात्रा में कालेधन की जनक मानी जा रहीं उक्त 500 कंपनियों के खिलाफ एक अप्रैल को की गई कार्रवाई के सिलसिले में ही इन दोनों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया है।

क्या है

1. इसी के साथ ईडी ने देशभर के बैंक खातों में 20 करोड़ रुपये की जमा राशि को भी फ्रीज कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि रेड्डी बेंगलुरु में औद्योगिक उत्पादन में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और भारत व दुबई मंद 20 से ज्यादा शेल कंपनियों की स्थापना के पीछे उसका ही दिमाग था। उसने फर्जी व जाली दस्तावेजों के सहारे और पहचान बदलकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकों से 70 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज भी हासिल कर लिया था। उसने जानबूझ कर बैंकों से लिया कर्ज नहीं चुकाया और पीएमएलए के तहत उसके खिलाफ तीन मामले दर्ज हैं। फिलहाल, विशेष अदालत ने उसे दो दिनों के लिए ईडी की हिरासत में दे दिया है।
2. लियाकत अली को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शेल कंपनियों के जरिये विदेशी मुद्रा बाहर भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बिना कोई वास्तविक आयात किए जाली बिलों के आधार पर उसने आठ शेल कंपनियों के मार्फत 1,17,78,120 अमेरिकी डॉलर (करीब 78 करोड़ रुपये) भारत के बाहर भेजकर चेन्नई स्थित इंडियन बैंक के साथ धोखाधड़ी की। इंडियन बैंक के अलर्ट पर चेन्नई कस्टम्स ने जांच में बिलों को फर्जी पाया और विस्तृत जांच के लिए मामला ईडी को संदर्भित कर दिया।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

सरकार ने ऑपरेशन क्लीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पिछले साल नवंबर में नोटबंदी के लागू होने से लेकर 10 जनवरी तक कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने 5400 करोड़ रुपए की श्अघोषित आयश का पता लगाया है। सरकार ने नोटबंदी के बाद 'विभिन्न गड़बड़ियों' का भी जिक्र किया जिसमें सोना खरीदने के लिए पुराने नोटों का प्रयोग शामिल है।

क्या है

1. कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा छापेमारी और बरामदगी की जानकारी देते हुए सरकार ने कहा कि 9 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 के बीच नोटबंदी काल के बाद आयकर विभाग ने 31 जनवरी को इस दौरान जमा नकदी के ई-सत्यापन हेतु डेटा विश्लेषण के लिए 'ऑपरेशन क्लीन मनी' शुरू किया।
2. वित्त मंत्रालय ने हफलनामा में कहा कि 9 नवंबर 2016 से 10 जनवरी 2017 के बीच ही आयकर विभाग ने विभिन्न लोगों पर 1100 से अधिक छापे मारे या सर्वेक्षण किए। उन्होंने कहा कि इस दौरान 'बैंक खातों में जमा बड़ी राशि की संदिग्ध नकदी' के सत्यापन हेतु 5100 से अधिक नोटिस जारी किये गए।
3. हलफनामे में कहा गया, छापे और अन्य कड़े कदम लागू करने के परिणामस्वरूप, आयकर विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों ने 610 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी (इसमें 513 करोड़ रुपए की नकदी जिसमें से 110 करोड़ रुपए की नई करंसी शामिल है) और कीमती वस्तुएं जब्त कीं।
4. इसमें कहा गया, 'इन कार्रवाइयों में पता लगाई अघोषित आय 5400 करोड़ रुपए से अधिक की है।' इसमें कहा गया कि 1100 छापों और सर्वेक्षणों में से 400 से अधिक मामले कानून के अनुरूप आगे की कार्रवाई के लिए प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को भेजे गए।
5. हलफनामे के अनुसार इस अभियान से करीब 18 लाख लोगों की ऑनलाइन सत्यापन के लिए पहचान हुई जो करदाता प्रोफाइल के अनुरूप नजर नहीं आए।
6. फिलहाल 8.38 लाख अलग-अलग पैन, लोगों से 12 लाख से अधिक आनलाइन प्रतिक्रिया मिली हैं। हलफनामे में कहा गया कि अगर उचित स्पष्टीकरण दिया जाता है तो उचित विश्लेषण और जांच के बाद सत्यापन बंद किया जा रहा है।
7. इसी तरह से जहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में धनराशि जमा की गई है तो भी सत्यापन बंद किया जा रहा है। इसमें कहा गया कि करीब 18 लाख अति जोखिम वाले मामलों में से 3.78 लाख से अधिक का पता लगाया है और आकलन एवं जांच के लिए इन्हें लिया गया है।

'जीएसटी लागू होने पर बनेगा ग्राहक कल्याण कोष'

बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने पर ग्राहकों के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कोई भी कारोबारी या सेवा प्रदाता ग्राहकों के हितों को नुकसान न पहुंचा सके, इसके लिए सरकार विशेष उपाय करने जा रही है। सरकार एक जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद एक 'ग्राहक कल्याण कोष' स्थापित करेगी। इस कोष से महिलाओं, आदिवासी और दलितों के उन संगठनों को अनुदान मिलेगा जो ग्राहकों के हितों में काम कर रहे हैं। साथ ही ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए काम करने वाले सामान्य संगठन और केंद्र व राज्य सरकारों के विभाग भी इस कोष से अनुदान प्राप्त कर सकेंगे।

क्या है

1. केंद्रीय जीएसटी कानून, 2017 की धारा 57 के तहत ग्राहक कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। इस कानून की धारा 58 में कोष के उपयोग के बारे में प्रावधान किए गए हैं। जीएसटी का उचित अधिकारी जब यह निश्चित कर ले कि रिफंड की राशि का भुगतान असेसी को नहीं किया जा सकता, तब वह इस राशि को 'ग्राहक कल्याण कोष' में ट्रांसफर करने का आदेश जारी कर सकता है।
2. सरकार ने जीएसटी के रिफंड संबंधी जिन नियमों का मसौदा तैयार किया है, उसमें इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिया है। इन नियमों यह भी बताया गया है कि ग्राहक कल्याण कोष का इस्तेमाल किस तरह किया जाए। यह फैसला करने के लिए एक स्थाई समिति बनाई जाएगी जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव होगा। साथ ही इसमें कुछ सदस्य भी होंगे। यह समिति उन उपायों की सिफारिश करेगी जिसके जरिए ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए इस कोष का इस्तेमाल किया जा सके। समिति को तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करनी होगी।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

3. खास बात यह है कि महिलाओं, आदिवासियों और दलितों द्वारा संचालित ग्राहकों के सहकारी समितियों, गांव और मंडल स्तर की समितियों को इस कोष से अनुदान मिल सकेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी इस कोष से अनुदान प्राप्त कर सकेंगी। हालांकि इनको यह राशि ग्राहकों के हितों की रक्षा के उपायों पर खर्च करनी होगी।
4. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण परिषद (सीसीपीसी) और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआइएस) इस कोष से अनुदान देने के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश तैयार कर जीएसटी परिषद को सौंपेंगे।

देश में 826 आवासीय परियोजनाएं कर रही हैं देरी का सामना

अपने घर का सपना किसका नहीं होता। मेहनत की गाढ़ी कमाई जोड़कर हर आदमी उस सपने को पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन तकलीफ तब होती है जब बिल्डर अपने वादों के मुताबिक तय समय पर घर की डिलीवरी नहीं करते हैं और फिर यहां के शुरू होती है फ्लैट खरीदारों की मुसीबत। एक रिपोर्ट की मानें तो देश में 826 आवासीय परियोजनाएं लगभग तीन से चार साल की देरी का सामना कर रही हैं।

क्या है

1. उद्योग संगठन एसोचौम के एक अध्ययन के मुताबिक, दिसंबर 2016 के अंत में 2,300 से अधिक रियल एस्टेट परियोजनाएं विकसित की गई थीं और इनमें से 826 आवास और 60 व्यावसायिक परियोजनाओं को देरी का सामना करना पड़ा।
2. अधिकतम देरी पंजाब में 48 महीनों की हुई। इसके बाद तेलंगाना (45 महीने), पश्चिम बंगाल (44 महीने), उड़ीसा (44 महीने) और हरियाणा(44 महीने)। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 42 महीने की देरी हुई। महाराष्ट्र में परियोजना डिलीवरी में 39 महीने की देरी हुई, वहीं कर्नाटक में 31 महीने यानी कम देरी देखने को मिली।
3. रियल स्टेट और हाउसिंग सेक्टर कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनमें हो रही देरी न केवल आवास क्षेत्र मंक निवेश को हतोत्साहित करती है, बल्कि देरी और भ्रष्टाचार का भी कारण बनती है।
4. एसोचौम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी के लिए एक सिंगल-विंडो सिस्टम लागू करना चाहिए।
5. अचल संपत्ति परियोजनाओं के नियामक की बजाय सरकार को एक सुविधा के रूप में कार्य करना चाहिए।

हर दिन बदलेंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें

सरकारी तेल कंपनियां 1 मई से देश के पांच शहरों में पेट्रोल-डीजल के दामों में प्रतिदिन बदलाव करने की योजना लागू करने जा रही हैं। ऐसा दुनिया के कई आधुनिक बाजारों में भी होता है। हर दिन तेल की कीमत बदलकर कंपनियां अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर पेट्रोल और डीजल बेच सकेंगी।

क्या है

1. पायलट प्रॉजेक्ट के तहत केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, राजस्थान के उदयपुर, झारखंड के जमशेदपुर (टाटा) और चंडीगढ़ में शुरुआत होगी।
2. अभी तक देश में सरकारी तेल कंपनियां हर पखवाड़े कीमतों पर फैसला लेती थीं। हर महीने की 1 और 16 तारीख को अंतरराष्ट्रीय बाजार में फ्यूल की कीमत और करंसी एक्सचेंज रेट के मुताबिक यहां दाम घटाए या बढ़ाए जाते थे।
3. पंपों तक कीमतों की जानकारी पहुंचाना पहले बहुत जटिल काम था। डीलर कंपनियों के फोन कॉल और फैक्स मेसेज के इंतजार में बैठे होते थे। इसके बाद सप्लाई ऑर्डर को बढ़ाने या कम करने के लिए दौड़ते थे। इससे सप्लायर्स को काफी परेशानी होती थी।

बिटकॉइन से मनीलांड्रिंग की जांच के लिए बनी समिति

क्या बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी से कालाधन सफेद हो रहा है? सरकार ने इस मामले की तह तक जाने के लिए एक समिति का गठन किया है जो वर्चुअल करेंसी से जुड़े तमाम मुद्दों पर विचार करेगी। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता वाली यह समिति तीन माह में अपनी रिपोर्ट देगी। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इस समिति में राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हैं।

क्या है

1. समिति भारत में बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी के मौजूदा फ्रेमवर्क तथा विदेशों में इस संबंध में कानूनी ढांचे पर विचार करेगी। साथ ही समिति इस बारे में सुझाव भी देगी कि बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी से उपभोक्ताओं के

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

हितों का किस तरह बचाव किया जाए। साथ ही इस बात पर भी विचार करेगी कि कहीं इससे कालाधन सफेद तो नहीं हो रहा।

2. उल्लेखनीय है कि वर्चुअल करेंसी पर दुनियाभर में विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं। रिजर्व बैंक ने भी समय-समय पर इस बारे में ग्राहकों तथा विभिन्न पक्षों को आगाह किया है।
3. कुछ समय पहले वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने संसद की स्थाई समिति को बताया था कि बिटकॉइन गैर कानूनी है और एक समिति इस मुद्दे पर गठित की गयी है। मंत्रालय के अधिकारियों ने कांग्रेस सदस्य वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली वित्त मामलों संबंधी संसदीय समिति को यह जानकारी दी है। वहीं बिटकॉइन का मुद्दा संसद में भी उठाया जा चुका है।
4. बिटकॉइन के मुद्दे को संसद में उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया का कहना है कि यह एक वैश्विक पोंजी स्कीम है। सरकार और आरबीआइ को इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस योजना में हजारों करोड़ रुपये लगे हैं। इसलिए लोगों को इसके प्रति सावधान करना चाहिए।

इंटरनेट दुनिया की सबसे बड़ी फंडिंग

प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने कहा कि टेनसेंट, ईबे, माइक्रोसॉफ्ट से 1.4 अरब डॉलर का वित्त जुटाने में सफल रहा है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि फ्लिपकार्ट के 10 साल के इतिहास में यह सबसे बड़ी फंडिंग है, साथ ही यह भारत के इंटरनेट क्षेत्र की भी सबसे बड़ी फंडिंग है। इस फंडिंग के बाद फ्लिपकार्ट की कीमत 11.6 अरब डॉलर हो गई है।

क्या है

1. इस निवेश से पहले फ्लिपकार्ट के निवेशकों में टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, नैस्पर समूह, एस्सेल पार्टनर्स और डीएसटी ग्लोबल शामिल थे।
2. फ्लिपकार्ट के संस्थापकों सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने एक बयान में कहा, यह सौदा फ्लिपकार्ट के लिए एक मील का पत्थर है।
3. यह सौदा कंपनी के प्रौद्योगिकी कौशल, अभिनव मानसिकता और पारंपरिक बाजारों में संभावनाओं को साबित करती है।
4. यह एक प्रचलित स्वीकृति है कि घरेलू तकनीक पारिस्थितिकी तंत्र वास्तव में संपन्न है और पूरे भारत में लोगों के दैनिक जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में सफल रहा है।
5. यह सौदा प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत में वाणिज्यिक परिवर्तन में तेजी लाने के हमारे संकल्प की पुष्टि करता है।

23 गुना बढ़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन

सरकार का नोटबंदी का फैसला असरदार साबित हो रहा है। नवंबर, 2016 से इस साल मार्च तक डिजिटल ट्रांजैक्शन की संख्या 23 गुना बढ़कर करीब 64 लाख पर पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल नवंबर में ही 500 और 1000 की पुरानी नोटों को बंद करने का एलान किया था। नीति आयोग ने बताया है कि पिछले साल नवंबर तक 101 करोड़ रुपये मूल्य के 2 लाख 80 हजार डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए थे। इसकी तुलना में ये डिजिटल ट्रांजैक्शन इस वर्ष मार्च में 23 गुना बढ़कर 63 लाख 80 हजार पर पहुंच गए। इन ट्रांजैक्शन का मूल्य 2,425 करोड़ रुपये रहा।

क्या है

1. आधार आधारित भुगतान नवंबर, 2016 में ढाई करोड़ से बढ़कर मार्च, 2017 में पांच करोड़ पर पहुंच गए। इस अवधि में तत्काल भुगतान सेवा (आइएमपीएस) से ट्रांजैक्शन की संख्या 3.6 करोड़ से बढ़कर 6.7 करोड़ पर पहुंच गई।
2. नोटबंदी के बाद सरकार ने डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए दो स्कीमें-लकी ग्राहक योजना और डिजि धन व्यापार योजना लांच की थीं। चालू वित्त वर्ष में 2,500 करोड़ के डिजिटल ट्रांजैक्शन का लक्ष्य तय किया गया है।
3. देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआइ ने 5.2 लाख एक्सेपटेंस टच प्वाइंट (एटीपी) तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। इन एटीपी में चार लाख डिजिटल पीओएस (भारत क्यूआर और आधार पे) शामिल हैं। साथ ही उसने तय किया है कि वह सरकार के डिजिटल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए 2017-18 में सामूहिक रूप से एक लाख करोड़ रुपये मूल्य के ट्रांजैक्शन का लक्ष्य प्राप्त करेगा।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

4. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) की मुखिया अरुंधती भट्टाचार्य ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान की दिशा में सरकार, बैंक और टेक्नोलॉजी कंपनियां साथ कदम बढ़ा रहे हैं। भारत एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदल रहा है। एसबीआइ डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
5. बैंक ने सरकार की ओर से लांच डिजिटल इंडिया और डिजि धन मेला अभियान के हिस्से के रूप में विभिन्न पहलों को लागू किया है। इनमें डिजिटल इको सिस्टम विकसित करने के लिए 110 गांवों को गोद लेना और नाबार्ड योजना के तहत 12,500 गांवों में 25 हजार टर्मिनल लगाने का लक्ष्य शामिल है।
6. मोबाइल फोन के जरिये भुगतान करने के लिए यात्रियों को प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की खातिर स्पाइसजेट ने एचएसबीसी इंडिया के साथ गठजोड़ किया है। नो फ्रिल एयरलाइन ने अपनी वेबसाइट पर भुगतान विकल्प के रूप में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआइ) लांच किया है।

विज्ञान और तकनिकी

भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाई कैंसर की दवा

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बार्क) के रामपत्री पौधे से कैंसर की एक नई दवा बनाई है जो दुनियाभर में कैंसर रोगियों के जीवन की रक्षा करने में मददगार हो सकती है। इससे पहले बार्क कैंसर के कोबाल्ट थेरेपी उपचार के लिए भाभाट्रोन नाम की मशीन भी बना चुका है। इसका इस्तेमाल दुनिया के कई देशों में हो रहा है। बार्क द्वारा रामपत्री नामक पौधे के अणुओं से बनाई गई कैंसर की दवा कर्क रोग के उपचार में क्रांति लाने में सहायक हो सकती है। रामपत्री से बनाई गई कैंसर की दवा का परीक्षण चूहों पर किया जा चुका है।

क्या है

1. यह दवा फेफड़े के कैंसर और बच्चों में होने वाले दुर्लभ प्रकार के कैंसर न्यूरोब्लास्टोमा के उपचार में काफी असरदार साबित हो सकती है। न्यूरोब्लास्टोमा एक ऐसा कैंसर है जिसमें वक्क ग्रंथियों, गर्दन, सीने और रीढ़ की नर्व कोशिकाओं में कैंसर कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं।
2. इस दवा को ईजाद करने वाले बार्क के विकिरण एवं स्वास्थ्य विज्ञान विभाग के बिरिजा शंकर पात्रो ने बताया कि रामपत्री फल के अणुओं में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने की क्षमता होती है।
3. यह विकिरण के कारण बेकार हुई कोशिकाओं को भी दुरस्त करने में मदद करते हैं। बार्क कई वर्षों से औषधीय एवं मसालों के पौधों के अणुओं से कैंसर की दवा बनाने के काम में लगा था। इसी कड़ी में मुंबई के अणुशक्ति नगर स्थित केंद्र ने रेडियो प्रोटेक्टर और रेडियो मॉडिफाइर नाम से दवाएं बनाई हैं।

उपलब्धि

1. रामपत्री से बनाई गई दवा बीमारी के इलाज में क्रांति लाने में सहायक होगी
2. रामपत्री फल के अणुओं में होती है कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने की क्षमता

4. रामपत्री भारत के पश्चिम तटीय क्षेत्र में पाया जाने वाला पौधा है जिसका वनस्पति वैज्ञानिक नाम मिरिस्टिका मालाबारिका है। इसे पुलाव और बिरयानी में सुगंध के लिए मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

घास से बने ईधन से उड़ते विमान

जैव ईंधन के विकास में जुटे वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता मिली है। वैज्ञानिकों ने घास से बने जैव ईधन का विकास किया है। इसका नाम 'ग्रासोलिन' रखा गया है। उनका दावा है कि भविष्य में घास से पैदा ईधन से विमान उड़ते दिख सकते हैं।

क्या है

1. शोधकर्ताओं ने उन विधियों को परखा जिसमें घास से ईधन बनाया जा सकता है। बेल्जियम की गेंट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता वे कर्न खोर ने कहा कि अभी घास का मुख्य रूप से इस्तेमाल पशुओं के चारे के तौर पर किया जाता है। इसका उपयोग जैव ईधन के तौर पर भी किया जा सकता है। घास ऊर्जा का बड़ा स्त्रोत भी बन सकती है।
2. वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल घास से बेहद कम मात्रा में ही जैव ईधन बनाया जा सकता है। घास को ईधन के रूप में तब्दील करने की मौजूदा प्रक्रिया भी महंगी है। अगर इस दिशा में और शोध किया जाए तो लागत को कम किया जा सकता है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

3. शोधकर्ताओं के अनुसार, पहले घास की जैव क्षमता को बेहतर कर इसमें बैक्टीरिया को मिलाया जाता है। इससे घास में मौजूद शुगर लैक्टिक एसिड में बदल जाता है।
4. लैक्टिक एसिड दूसरे कंपाउंड जैसे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक (पीएलए) या ईंधन बनाने वाले रसायन के तौर पर काम कर सकता है। इसके बाद लैक्टिक एसिड पहले कैप्रोइक एसिड और फिर डीकेन में बदल जाता है। यह डीकेन विमानन ऊर्जा के तौर पर उपयोग किया जा सकता है।

डार्क मैटर के अस्तित्व पर ही उठा सवाल

ब्रह्माण्ड का सबसे रहस्यमयी हिस्सा माने जाने वाले डार्क मैटर को लेकर एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि डार्क मैटर जैसी किसी वस्तु या ऊर्जा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब तक वैज्ञानिक मानते रहे हैं कि ब्रह्माण्ड का 68 फीसद हिस्सा डार्क मैटर से ही बना है।

क्या है

1. 1920 में गैलेक्सियों के वेग के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला था कि ब्रह्माण्ड का लगातार विस्तार हो रहा है। ब्रह्माांड का निर्माण एक छोटे बिंदु से हुआ था।
2. पिछली सदी के मध्य तक वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि गैलेक्सियों के अंदर तारों की गति के लिए किसी अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता है। इसी के आधार पर डार्क मैटर की उपस्थिति का सिद्धांत दिया गया।
3. 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने बौने तारों के विस्फोट के अध्ययन के बाद यह माना कि ब्रह्माण्ड में 68 फीसद हिस्सा डार्क एनर्जी का है और यह ब्रह्माण्ड में लगातार हो रहे फैलाव के लिए जिम्मेदार है।
4. अब हंगरी की इओटवोस लोरेंड यूनिवर्सिटी के पीएचडी छात्र गेबर रैज की अगुआई में शोधकर्ताओं ने डार्क मैटर या डार्क एनर्जी के सिद्धांत पर सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है ब्रह्माण्ड का आदर्श मॉडल उसके विस्तार को तो समझाता है, लेकिन उसकी संरचना में होने वाले बदलाव को समझाने में असफल है।
5. अगर ब्रह्माण्ड की संरचना में हो रहे बदलाव पर गौर करें तो डार्क मैटर जैसी किसी अदृश्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
6. ब्रह्माण्ड के विस्तार को बिना डार्क एनर्जी की उपस्थिति के ही समझना संभव हो सकता है। यह शोध रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मासिक नोटिसों में प्रकाशित किया गया है।

फास्ट न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर

अंतरिक्ष में भेजे गए क्रू की सुरक्षित वापसी के उद्देश्य से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक नई डिवाइस का अविष्कार किया है। यह डिवाइस न्यूट्रॉन के विकिरण प्रदर्शन पर निगरानी रखेगी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर इसका परीक्षण किया जा रहा है।

क्या है

1. फास्ट न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर को न्यूट्रॉन की ऊर्जा का पता लगाने तथा इसे मापने के लिए डिजाइन किया गया है। अलबामा के हंट्सविले में नासा के मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर के मार्क क्रिस्टल ने बताया, अंतरिक्ष में कई प्रकार के रेडियशन होते हैं।
2. सुपरनोवा या ब्लैक होल, एक्स-रे और अन्य कणों द्वारा निर्मित गामा किरणों का पता लगाने के लिए पहले से ही बेहतरीन उपकरण मौजूद हैं, लेकिन हमें मानवीय जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए न्यूट्रॉन रेडियशन का पता लगाने तथा इसका उपाय ढूढ़ने की आवश्यकता है।
3. जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उस तरह से न्यूट्रॉन की पहचान करने वाली तकनीक विकसित नहीं हो पाई है।
4. न्यूट्रॉन रेडियशन तब होता है जब सूर्य और हमारे सौर मंडल से निकलने वाले उच्च ऊर्जा कण अन्य कणों के संपर्क में आते हैं।
5. लेकिन आवेशित कणों में परिवर्तित होने से पहले ये केवल 13 मिनट तक ही प्रभावी रहते हैं।
6. फास्ट न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर मुख्य रूप से एक निष्क्रिय टूल है, जो न्यूट्रॉन से टकराने का इंतजार करता है। इसमें प्लास्टिक स्किनटिलेटर के साथ एक एल्यूमीनियम धातु भी होती है जो डिवाइस से टकराते समय न्यूट्रॉन को धीमा कर देती है।

शनि ग्रह के चंद्रमा पर जीवन के अनुकूल माहौल

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि के चंद्रमा एनसेलेडस पर जीवन के अनुकूल माहौल होने का पता चला है। इस पर कुछ ऐसी रासायनिक ऊर्जा की पहचान की गई है जिससे जीवन को समर्थन मिल सकता है। शनि ग्रह का अध्ययन कर रहे नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान और हब्बल स्पेस टेलीस्कोप से उसके चंद्रमाओं के बारे में नई जानकारी सामने आई है।

क्या है

1. शनि ग्रह के कम से कम 62 चंद्रमा हैं। इनमें से एनसेलेडस छठा सबसे बड़ा चंद्रमा है। नासा के साइंस मिशन डायरेक्टोरेट के सहायक प्रशासक थॉमस जर्बुचेन ने कहा कि हम एक स्थान की पहचान करने के करीब हैं जहां जीवन योग्य वातावरण के लिए कुछ जरूरी तत्व हो सकते हैं।
2. कैसिनी मिशन के वैज्ञानिकों ने एलान किया है कि एनसेलेडस पर एक तरह की रासायनिक ऊर्जा मौजूद हो सकती है जो जीवन के अस्तित्व के लिए सहायक हो सकती है।
3. एनसेलेडस की बर्फीली सतह से हाइड्रोथर्मल गतिविधि के चलते हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है जो जीवन के योग्य रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम है। ऐसे में यह प्रतीत होता है कि वहां पर्याप्त हाइड्रोजन की मौजूदगी से सूक्ष्मजीव का अस्तित्व हो सकता है।
4. नासा की जेट प्रोपल्शन लैब के वैज्ञानिक लिंडा स्पाइल्कर ने कहा, 'शनि ग्रह के चंद्रमा पर जीवन के अनुकूल रासायनिक ऊर्जा की मौजूदगी की पुष्टि पृथ्वी से परे जीवन की खोज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।'

1500 प्रकाश वर्ष दूर नए तारे का हुआ जन्म

अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से लगभग 1500 प्रकाश वर्ष दूर एक विस्फोटक तारे के जन्म की तस्वीरें कैद की हैं। इससे अंतरिक्ष में तारों के जन्म के बारे में नई जानकारियां मिलेंगी। शोधकर्ताओं के अनुसार, हरों साल पूर्व दो प्रोटो-स्टार की बेहद करीबी टक्कर हुई थी। इससे एक धमाका हुआ और दोनों के तारा निर्माण क्षेत्र अलग-अलग हो गए। प्रोटो-स्टार गैसों का एक संघनित पिंड होता है। यह तारे के निर्माण की आरंभिक अवस्था होती है।

क्या है

1. चिली में अटाकामा लार्ज मिलीमीटर-सबमिलीमीटर ऐरे टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने इस धमाके से बिखरे मलबे का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि लगभग एक लाख साल पहले निर्माण शुरू होने के कुछ ही समय बाद ओरियन मॉलिक्यूलर क्लाउड के कई प्रोटो स्टार गुरुत्वीय आधार पर एक दूसरे के बेहद निकट आ गए।
2. इससे वे एक-दूसरे से छू गए या फिर टकरा गए। इससे भारी विस्फोट हुआ। इससे कई अन्य प्रोटो स्टार एवं गैस की सैंकड़ों रोशनियां 150 किलोमीटर प्रति सेकेंड से अधिक गति से अंतरिक्ष में निकलीं।
3. अमेरिका में कोलोरेडो यूनिवर्सिटी के जॉन बैली ने कहा, कभी शांत रहे तारा निर्माण क्षेत्र में जो हमने देखा, वह अमेरिका में 4 जुलाई को की जाने वाली आतिशबाजी के समान था।

पहले थ्री-पैरेंट बेबी की तकनीक हुई सार्वजनिक

दुनिया के पहले थ्री-पैरेंट बेबी (तीन अभिभावकों की संतान) के जन्म की आइवीएफ तकनीक सार्वजनिक हो गई है। वैज्ञानिकों ने पिछले साल छह अप्रैल को न्यूयॉर्क में इस तकनीक से एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने में सफलता हासिल की थी।

क्या है

1. वैज्ञानिकों के मुताबिक, बच्चे के जन्म में माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी (एमआरटी) की प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसकी मदद से माइटोकॉन्ड्रिया की गंभीर खामी के कारण होने वाले लीफ सिंड्रोम से बच्चे को बचाया जा सका। न्यूयॉर्क स्थित न्यू होप फर्टिलिटी सेंटर के जॉन झेंग और उनकी टीम ने इस प्रक्रिया को अंजाम दिया था।
2. वैज्ञानिकों ने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। बच्चे की मां के माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ खामी है। यही खामी गर्भधारण के बाद बच्चे में जानलेवा बन जाती है। इसी कारण महिला का चार बार गर्भपात हो गया था। दो बार उसने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन वे जीवित नहीं रह सके।
3. नई तकनीक में मां के अंडाणु के एक न्यूक्लियर जीनोम को अन्य महिला के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया वाले अंडाणु के जीनोम से बदल दिया गया। इसके बाद अंडे का निषेचन कर उसे मां के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया गया।
4. इस तरह से बच्चे का जन्म दो मां और एक पिता से हुआ। दंपती जॉर्डन के रहने वाले हैं। इस तकनीक की सफलता से भविष्य में आनुवांशिक रूप से होने वाली जन्मजात बीमारियों से बच्चों को बचाना संभव हो सकता है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

आईआईटी दिल्ली के छात्र विकसित कर रहे हैं हाइब्रिड विमान

आईआईटी दिल्ली के मैकेनिकल इंजिनियरिंग के छात्र इन दिनों अमेरिका में हाइब्रिड विमान विकसित करने की जुगत में लगे हैं। 2020 की शुरुआत में 1,100 किलोमीटर लंबी क्षेत्रीय उड़ानों के लिए भारत में उसे बेचने की उम्मीद है।

क्या है

1. किर्कलैंड (वाशिंगटन) के सीईओ और संस्थापक आशीष कुमार, जोनुम एयरो आधारित क्षेत्रीय हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक विमान विकसित कर रहे हैं, जिनकी सीमा 2030 तक 1600 किमी तक होगी। बोइंग और जेटब्लू इनका समर्थन कर रहे हैं।
2. कॉर्नेल विश्वविद्यालय से यांत्रिक और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी करने वाले कुमार ने बताया, हम उप -20 सीटर हाइब्रिड विमान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले दो साल में पहला प्रोटोटाइप उड़ जाएगा और 2020 के शुरुआती दिनों में व्यावसायिक उत्पादन शुरू होगा।
3. कंपनी का सपना हर समुदाय के लिए तेजी से और सस्ती यात्रा लाने के लिए 1000 मील के इलेक्ट्रिक एयर नेटवर्क का विकास करना है।
4. हाइब्रिड विमान में 80 फीसद कम उत्सर्जन होगा। कुमार ने कहा इन विमानों की कम परिचालन लागत है। एयरलाइंस को सस्ते किरायों की पेशकश की जाएगी। इसके लिए हम भारत को एक बड़े पैमाने पर देख रहे हैं।

धरती जैसे ग्रह पर पहली बार मिला वायुमंडल

खगोलविदों ने धरती जैसे दिखने वाले एक ग्रह पर पहली बार वायुमंडल की मौजूदगी का पता लगाया है। यह ग्रह हमारी धरती से महज 39 प्रकाश वर्ष दूर है। हमारे सौर मंडल के बाहर जीवन का पता लगाने की दिशा में यह उल्लेखनीय कदम है।

क्या है

1. जर्मनी के मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनोमी के वैज्ञानिकों ने जीजे 1132बी नामक ग्रह का अध्ययन किया है। यह ग्रह हमारी धरती के आकार से 1.4 गुना ज्यादा बड़ा है।
2. उनका आंकलन है कि यह एक तारे की परिक्रमा करता है। जब यह ग्रह उस तारे के सामने से गुजरता है तब उसकी रोशनी के प्रभाव से इसकी चमक और वायुमंडल में थोड़ी कमी आ जाती है।
3. शोधकर्ताओं ने बताया कि जीजे 1132बी का द्रव्यमान और रेडियस लगभग पृथ्वी के समान है। इस तरह के ग्रह पर पहली बार वायुमंडल का पता चला है। इस ग्रह का आकार भी हमारी धरती के समान है। मौजूदा पर्यवेक्षण में इसके वायुमंडल के विश्लेषण के लिए पहला कदम उठाया गया है।
4. जीजे 1132बी हमसे 39 प्रकाश वर्ष दूर रेड ड्वार्फ स्टार जीजे 1132 की परिक्रमा करता है। शोधकर्ताओं की टीम ने चिली में स्थित यूरोपीय सदर्न ऑब्जर्वेटरी की दूरबीन की मदद से इस ग्रह का अवलोकन किया।
5. अभी इतना पर्याप्त आंकड़ा नहीं मिला है जिससे इस नतीजे पर पहुंचा जा सके कि जीजे 1132बी पृथ्वी के कितना समान है।

विविध

संयुक्त राष्ट्र में सबसे कम उम्र की शांति दूत

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को संयुक्त राष्ट्र का शांति दूत चुना गया है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसी को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। 19 वर्षीय मलाला यह सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की शांति दूत बनेंगी। अगले हफ्ते एक समारोह में उन्हें आधिकारिक रूप से जिम्मेदारी दी जाएगी।

क्या है

1. मलाला के चयन पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, गंभीर खतरे के बावजूद मलाला ने महिलाओं, लड़कियों और सभी के अधिकारों के लिए अटल प्रतिबद्धता दिखाई।
2. लड़कियों की शिक्षा के लिए उनके प्रयास ने दुनियाभर में बहुत से लोगों को प्रोत्साहित किया है।
3. मलाला अक्टूबर 2012 में सुर्खियों में आई थीं, जब तालिबान आर्तकियों ने उन्हें गोली मार दी थी। लड़कियों की शिक्षा के लिए मलाला के प्रयास के विरोध में तालिबान ने उन्हें निशाना बनाया था।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

4. हमले में गंभीर रूप से घायल मलाला ने ठीक होने के बाद लड़कियों की शिक्षा के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा।
5. 2014 में उन्हें भारत में बच्चों के अधिकारों और शिक्षा के लिए काम करने वाले कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया।

सिंधु ने लिया हार का बदला

इंडिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन के फाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु ने अपनी चिर प्रतिद्वंद्वी स्पेन की कैरोलिना मारिन को एक बार फिर हार का मजा चखाया है। रियो ओलिंपिक के फाइनल में कैरोलिना मारिन से मिली हार के बाद सिंधु ने उन्हें दूसरी बार हराया है। लेकिन रियो के बाद यह पहला मौका था, जब सिंधु, मारिन से किसी खिताब के लिए फाइनल मुकाबले में भिड़ी हों। सिंधु ने इंडिया ओपन के फाइनल मुकाबले में कैरोलिना को 21-19, 21-16 से मात देकर यह खिताब अपने नाम कर लिया। यह पहली बार है, जब उन्होंने इंडिया ओपन का खिताब जीता हो।

क्या है

1. इससे पहले सिंधु ने 2016 के अंत तक ही कैरोलिना मारिन से अपनी रियो की हार की बदला ले लिया था। दुबई वर्ल्ड मास्टर्स सुपर सीरीज फाइनल्स 2016 में पीवी सिंधु ने क्वॉर्टर फाइनल मुकाबले में मारिन को 21-17, 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी।
2. रियो ओलिंपिक के फाइनल मुकाबले में सिंधु को कैरोलिना से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। हालांकि यह ओलिंपिक में उनका पहला मेडल था।
3. नई दिल्ली में खेले गए मुकाबले में यह 10वां मौका था, जब दोनों खिलाड़ियों ने कोर्ट पर एक-दूसरे से लोहा लिया। इस मुकाबले में सिंधु की जीत के बाद, अब दोनों खिलाड़ी 5-5 बार एक-दूसरे के खिलाफ जीत चुकी हैं।

सबसे उम्रदराज अंतरिक्ष यात्री का अभियान

दुनिया की सबसे उम्रदराज और सर्वाधिक अनुभवी महिला अंतरिक्ष यात्री पेगी ह्विटसन का अभियान बढ़ा दिया गया है। ह्विटसन को तीन महीने और अंतरिक्ष में रहने का मौका मिलेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यह जानकारी दी है।

क्या है

1. ह्विटसन ने हाल ही में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का सबसे ज्यादा बार स्पेस वाक का रिकॉर्ड तोड़ा था।
2. ह्विटसन सितंबर तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आइएसएस) पर रहेंगी। 57 वर्षीय ह्विटसन पिछले साल नवंबर में अंतरिक्ष में पहुंची थीं। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार उन्हें जून में पृथ्वी पर वापस लौटना था। नासा और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच हुए समझौते के तहत उन्हें वहां तीन महीने और रहने का मौका मिला है। उनका यह तीसरा मिशन अब लगभग 10 माह का होगा।
3. वैज्ञानिक लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से उनके शरीर में होने वाले संभावित परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अंतरिक्ष में एक साल गुजारने वाले अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली पर इस संबंध में अध्ययन किया जा चुका है।

64वां नैशनल अवॉर्ड

64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा शुरू हुई, जिसमें 2016 में रिलीज हुई फिल्मों से चुनिंदा विजेताओं के नामों का ऐलान किया गया है। राम माधवानी निर्देशित सोनम कपूर स्टारर 'नीरजा' को जहां बेस्ट हिन्दी फीचर फिल्म का अवॉर्ड मिला, वहीं अक्षय कुमार को 'रुस्तम' के लिए बेस्ट ऐक्टर अवॉर्ड से नवाजा गया। अजय देवगन की फिल्म 'शिवाय' को बेस्ट वीएफएक्स के लिए अवॉर्ड दिया गया। इसके अलावा 'नीरजा' में सोनम कपूर के शानदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें स्पेशल मेंशन अवॉर्ड (स्पेशल जूरी अवॉर्ड) दिया गया। राजधानी दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया सेंटर आयोजित इस कार्यक्रम में जाने-माने हास्य फिल्मकार प्रियदर्शन इस साल फीचर फिल्म की श्रेणी में जूरी के अध्यक्ष के तौर पर शामिल थे, जबकि सिनेमटॉग्रफर और राइटर राजू मिश्रा नॉन-फीचर कैटिगरी के अध्यक्ष थे। इस लिस्ट में पिछले साल रिलीज हुई करीब 300 से ज्यादा फिल्में शामिल थीं। बेस्ट कैटिगरी के लिए विनर्स को चुनने का काम मार्च से ही शुरू हो चुका था। गौरतलब है कि अवॉर्ड डिस्ट्रिब्यूशन सेरिमनी का आयोजन 3 मई 2017 को किया जाना है।

फीचर फिल्म अवॉर्ड की लिस्ट

1. बतौर निर्देशक बेस्ट डेब्यू फिल्म : दीप चौधरी (अलीफा)
2. बेस्ट पॉप्युलर एंटरटेनिंग फिल्म - सतमानम भवती
3. बेस्ट स्टंट कोरियॉग्राफर- पीटर हीन (पुलीमुरुगन)

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

4. बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म- धनक (हिन्दी)
5. सोशल मुद्दे पर बनी बेस्ट फिल्म- पिंक
6. बेस्ट डायरेक्शन- राजेश (वेंटिलेटर)
7. बेस्ट डायरेक्शन- राजेश मपुस्कर (वेंटिलेटर)
8. बेस्ट ऐक्टर- अक्षय कुमार (रुस्तम)
9. बेस्ट ऐक्ट्रेस- सुरभि लक्ष्मी (मिन्नामीनुनगु)
10. बेस्ट सपॉर्टिंग ऐक्ट्रेस- जायरा वसीम (दंगल)
11. बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट- आधिश प्रवीण (कुंजू देवम), साज (नूर इस्लाम), मनोहरा (रेलवे चिल्ड्रन)
12. बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर- सुंदर अय्यर (जोकर)
13. बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर- थुमे जाके
14. बेस्ट स्क्रीनप्ले (ऑरिजनल)- श्याम पुष्करन (महेशिन्ते प्रतिकारम)
15. बेस्ट स्क्रीनप्ले (अडैप्टेड)- संजय कृष्णाजी पटेल (दशक्रिया)
16. बेस्ट एडिटिंग- रामेश्वर वेंटिलेटर
17. साउंड डिजाइनर- जयदेवन (काडू पूकुन्ना नेरम)
18. बेस्ट प्रॉडक्शन डिजाइन- 24
19. बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर- सचिन (मराठी फिल्म)
20. बेस्ट इन्वाइरनमेंटल फिल्म जिसमें ऐग्रिकल्चर भी शामिल है- द टाइगर हू क्रॉस्ड द लाइन
21. बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट- एमके रामकृष्ण
22. बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन- बाबू पद्मनाभ (कन्नड़ अलमा)
23. स्पेशल मेंशन- कद्वी हावा
24. मुक्ति भाव (हिंदी)
25. मजीरठी केकी (असमिया)
26. नीरजा- सोनम कपूर
27. स्पेशल जूरी अवॉर्ड पुलिमुरुगन के लिए मोहनलाल को, जनता गड़गे और मुंथिरिवल्लिकल थलिरक्कुम्बोल को

क्षेत्रिय भाषा की बेस्ट फीचर फिल्में

1. मादीपुर (तुलु)
2. जोकर (तमिल)
3. रॉन्गसाइड राजू (गुजराती)
4. पेल्ली चुपुलु (तेलगू)
5. दशक्रिया (मराठी)
6. बिसर्जन (बंगाली)
7. महेशिंते प्रतिकरम (मलयालम)
8. के सरा सरा (कोंकणी)
9. रिजर्वेशन (कन्नड़)
10. नीरजा (हिंदी)

अन्य

1. बेस्ट नॉन फीचर फिल्म- फायरफ्लाइज इन द अबिस
2. बेस्ट एजुकेशनल फिल्म- द वॉटरफॉल
3. बेस्ट शॉर्ट फिक्शन- आबा
4. बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का अवॉर्ड जी. धनंजय को
5. सिनेमा पर बेस्ट किताब- लता सुर गाथा
6. उत्तर प्रदेश को देश का फिल्म फ्रेंडली राज्य घोषित किया गया
7. झारखंड को मिला स्पेशल मेंशन
8. फीचर फिल्म अवॉर्ड की कैटिगरी के लिए जूरी मेंबरों ने 26 भाषा की 344 फिल्मों को कंसिडर किया था

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

धूम्रपान से मौत में दुनिया के टॉप चार देशों में भारत

धूम्रपान के विज्ञापन के साथ ही सिनेमाघरों में किसी फिल्म की शुरुआत होती है। धुंआ न सिर्फ आपको बल्कि आपके अपनों के लिए जानलेवा है, फिल्मों से पहले दिखाए जानें वाले इस विज्ञापन का संदेश लगता नहीं हर किसी के समझ आ रहा है। अगर आता तो भारत धूम्रपान से मरने वाले टॉप चार देशों में से एक नहीं होता।

क्या है

1. पत्रिका 'द लैनसेट' में प्रकाशित ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज (जीबीडी) के अनुसार 2015 में दुनियाभर में जान गंवाने वाले 64 लाख लोगों में से 11.5 फीसद की मौत का कारण धूम्रपान है।
2. इनमें से 52.2 फीसद लोगों की मौत चीन, भारत, अमेरिका और रूस में हुई। पुरुषों के धूम्रपान करने के मामले में चीन, भारत और इंडोनेशिया तीन अग्रणी देश हैं।
3. 2015 में धूमपान करने वाले 51.4 फीसद पुरुष इन्हीं देशों के थे। दुनिया में धूमपान करने वाली कुल आबादी का 11.2 फीसद हिस्सा भारत में रहता है।
4. 2005 की तुलना में 2015 में धूम्रपान से होने वाली मौतों में 4.7 फीसद की वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, धूमपान इस समय अक्षमता का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन गया है। इससे पहले तक इसे तीसरा सबसे बड़ा कारण माना जाता रहा है।
5. अध्ययन 1990 से 2015 के बीच 195 देशों में धूम्रपान करने की आदतों पर आधारित है। अध्ययन के अनुसार, महिलाओं द्वारा धूम्रपान करने के मामले में तीन अग्रणी देश अमेरिका, चीन और भारत हैं।
6. इन तीनों देशों में धूम्रपान करने वाली महिलाओं की 27.3 फीसद आबादी रहती है। अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि धूम्रपान के खिलाफ लड़ाई जीत से बहुत दूर है।
7. इस समय दुनियाभर में 25 फीसद पुरुष और 5.4 फीसद महिलाएं धूम्रपान करती हैं।

अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला जज पाई गई मृत

न्यूयॉर्क राज्य के सर्वोच्च न्यायालय की सहयोगी न्यायाधीश और पहली मुस्लिम न्यारयाधीश शैला अब्दुस सलाम हडसन नदी में मृत पाई गई। अधिकारियों ने बताया कि न्यूऔयॉर्क पुलिस को सूचना मिली थी कि ऊपरी मैनहट्टन के वेस्ट 132 स्ट्रीट के नजदीक घाट पर व्यक्ति तैरता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को बाहर निकाला गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

क्या है

1. शैला अब्दुास सलाम के पति ने बॉडी की शिनाख्त कर ली है। न्यू यॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक, साल 2013 से शैला 'स्टेट कोर्ट ऑफ अपील्सत' के सात न्यॉयाधीशों में से एक थीं।
2. इससे पहले, वह राज्य सुप्रीम कोर्ट के प्रथम अपीलीय डिवीजन में सहयोगी न्यायाधीश के रूप में लगभग चार साल तक कार्यरत थी और मैनहट्टन में एक राज्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में 15 साल तक काम किया। वह पहले शहर के कानून विभाग में एक वकील थीं।

'ऑपरेशन मेघदूत' के 33 साल

'ऑपरेशन मेघदूत', भारतीय सशस्त्र सेना के ऑपरेशन का एक कोड-नाम है। 33 साल पहले इसे आज ही के दिन (13 अप्रैल) शुरू किया गया था। 1984 में आज ही के दिन कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए सशस्त्र बलों ने अभियान छेड़ा था। यह सैन्य अभियान अनोखा था क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी युद्धक्षेत्र में पहली बार हमला शुरू किया गया था। सेना की कार्रवाई के परिणामस्वरूप भारतीय सैनिक पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण हासिल कर रहे थे।

क्या है

1. सियाचिन के एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है, तो दूसरी तरफ चीन की सीमा अक्साई चीन इस इलाके को छूती है।
2. यह उत्तर पश्चिम भारत में काराकोरम रेंज में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर 76.4 किमी लंबा है और इसमें लगभग 10,000 वर्ग किमी विरान मैदान शामिल हैं।
3. 1974 में, पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर में पर्वतारोहण अभियानों की अनुमति देना शुरू कर दिया था। 1983 के वसंत तक, यह साफ हो गया था कि भारत को सियाचीन पर पैनी नजर बनाए रखने की जरुरत है।
4. इस दिन, ऑपरेशन मेघदूत शुरू करने वाले तत्कालीन कैप्टन संजय कुलकर्णी की अगुवाई में चार कुमाओं के एक दल ने बिलाफोंड ला में सियाचिन ग्लेशियर पर पहला भारतीय झंडा लहराया था।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

अब चांद और मंगल पर 3डी प्रिंटिंग से बनेगा घर

3डी प्रिंटिंग की तकनीक धरती ही नहीं, अंतरिक्ष में भी वैज्ञानिकों के लिए सहायक हो रही है। वैज्ञानिकों ने चांद और मंगल पर मिलने वाली मिट्टी से 3डी प्रिंटिंग के जरिये छोटे उपकरण से लेकर बड़े भवन तक बनाने की तकनीक विकसित की है। इस तकनीक की मदद से धरती से परे ग्रहों पर कॉलोनियां बनाना संभव हो सकता है।

क्या है

1. अमेरिका की नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मंगल और चांद की धूल जैसे कणों से 3डी प्रिंटिंग के जरिये विभिन्न आकृतियां बनाने में सफलता हासिल की है।
2. इस प्रक्रिया में 3डी पेंटिंग तकनीक का सहारा लिया गया। इस तकनीक से पहले लचीली अस्थियां, ग्रेफीन और कार्बन नैनोट्यूब बनाए जा चुके हैं।
3. सहायक प्रोफेसर रेमिल शाह ने कहा, धरती से इतर ग्रहों और चंद्रमा पर सीमित संसाधन ही उपलब्ध हैं। वहां रहने के लिए इन्हीं संसाधनों से व्यवस्था करने की आवश्यकता है।
4. हमारी 3डी पेंट तकनीक धरती से परे रहने की व्यवस्था बनाने में सक्षम है। 3डी प्रिंटिंग से तैयार रबड़ की तरह लचीली और मजबूत इन आकृतियों में 90 फीसद तक उन ग्रहों की धूल का प्रयोग होगा।

भारतीय ने जीता संयुक्त राष्ट्र चौलेंज में शीर्ष पुरस्कार

एक भारतीय साफ्टवेयर इंजीनियर ने संयुक्त राष्ट्र की श्ओपन सोर्स टूलश की वैश्विक प्रतियोगिता का शीर्ष पुरस्कार जीता है। इस टूल से यूजरों को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्तावों को प्रभावी तरीके से देखने और सदस्य देशों की मतदान प्रक्रिया को गहराई से समझने में मदद मिलेगी।

क्या है

1. अब्दुल कादिर राशिक ने अपने ओपेन सोर्स टूल श्ग्लोबल पॉलिसीश के लिए 'यूनाइट आइडियाज हैशटैग यूएनजीए विज टेक्स्टूअल एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन चौलेंज' को जीता है।
2. उनके इस प्रोटोटाइप टूल को सार्वजनिक किया जाएगा। इसे संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं और सदस्य देशों के साथ साझा किया जाएगा। उनके इस काम को अमेरिका के विदेश विभाग और संयुक्त राष्ट्र के सूचना व संचार प्रौद्योगिकी कार्यालय से मान्यता भी मिलेगा।
3. प्रतियोगिता में अर्जेंटीना के सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार मैक्सीमिलानो लोपेज दूसरे और फ्रांस के सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार थॉमस फोर्नेस तीसरे स्थान पर रहे।
4. यूनाइट आइडिया चौलेंज में बराबर हिस्सा लेने वाले अब्दुल ने इससे पहले अपने 'लिंक्स टू सस्टेनबल सिटीज' के लिए हैशटैग लिंक्स एसडीजी प्रतिस्पर्धा का शीर्ष पुरस्कार जीता था।
5. 'लिंक्स टू सस्टेनेबल सिटीज' सतत विकास लक्ष्यों की पहचान और कड़ियों का खाका खींचने में मददगार है।

तीसरे विश्व युद्ध से सहमी दुनिया

सीरिया में हुए रासायनिक हमले के बाद अमेरिका की सख्त सैन्य कार्रवाई से तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट नजर आने लगी है। डर का आलम यह है कि अमेरिका के मिसाइल हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है, दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। सीरिया में भड़की यह चिंगारी विकराल रूप लेकर कहीं विश्वयुद्ध में न तब्दील हो जाए, इसलिए विश्व नेताओं ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से तनाव न बढ़ाने की अपील की है।

क्या है

1. सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के कट्टर समर्थक रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सीरिया के एयरबेस पर अमेरिका के हवाई हमलों के बाद मध्य-पूर्व के अपने इस सहयोगी देश का एयर-डिफेंस मजबूत करने का फैसला किया है। इससे इस बात की आशंका बढ़ गई है कि सीरिया में जारी तनाव रूस और पश्चिमी देशों के बीच आर-पार की लड़ाई का कारण बन सकता है।
2. अमेरिका ने रासायनिक हमले के लिए सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को जिम्मेदार ठहराया है जबकि सीरियाई सेना इसके लिए विद्रोहियों को जिम्मेदार बता रही है।
3. रासायनिक हमले में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सख्त बयान जारी कर कहा था कि असद ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है और 'कुछ न कुछ होना चाहिए'।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

4. ट्रंप के इस बयान के कुछ ही घंटों के बाद गुरुवार को अमेरिकी सेना ने सीरिया के अल-शयरात एयरबेस पर 50 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें दागी। मिसाइल हमले में एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा है।
5. अमेरिका की इस कार्रवाई से रूसी राष्ट्रपति पुतिन भड़के हुए हैं। हमले से करीब आधे घंटे पहले अमेरिका ने रूस को सीरया में मिसाइल हमलों की जानकारी दी थी।
6. अल-शयरात एयरबेस पर अमेरिकी हमले के तुरंत बाद रूस ने अपने जंगी बेड़े ऐडमिरल ग्रिगोरोविच को ब्लैक सी से डायवर्ट कर दिया। शुक्रवार को ऐडमिरल ग्रिगोरोविच सीरिया पहुंच गया। यह जंगी बेड़ा क्रूज मिसाइलों और सेल्फ-डिफेंस सिस्टम से लैस है।
7. अमेरिकी मिसाइल हमलों के बाद रूसी और सीरियाई लड़ाकू विमानों ने विद्रोहियों के कब्जे वाले खान शेखों शहर में जबरदस्त हवाई हमले किए। इस बीच विश्व नेताओं ने रूस से और ज्यादा तनाव न भड़काने की अपील की है। फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रियों ने कहा कि हम नहीं चाहते कि तनाव और भड़के।
8. सीरिया पिछले 6 सालों से ज्यादा समय से गृहयुद्ध की चपेट में है। राष्ट्रपति बशर अल असद को लेकर दुनिया के देश साफ तौर पर दो खेमों में बंटे हुए हैं। असद पर विरोधियों और विद्रोहियों के सख्ती से दमन के आरोप लगते रहे हैं।
9. रूस के अलावा ईरान, उत्तर कोरिया, इराक, अल्जीरिया, वेनेजुएला, लेबनान और बेलारूस को असद का समर्थक माना जाता है।
10. दूसरी तरफ अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, कनाडा, सऊदी अरब, इजरायल और कतर जैसे मुल्क असद के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। यही वजह है कि अगर तनाव ज्यादा बढ़ा तो सीरिया की लड़ाई व्यापक रूप ले सकती है और सीरिया तीसरे विश्वयुद्ध का मैदान बन सकता है।

आज ही के दिन डूबा था टाइटैनिक जहाज

आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था। आरएमएस टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा पर निकला था। ऐसा कहा जाता था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकता। चार दिन के बाद 14 अप्रैल की रात 11 बजकर 40 मिनट पर चालक दल की लापरवाही से टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग इतना बड़ा था कि इससे टकराने से टाइटैनिक के निचले हिस्सों में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज के टकराने से लोग घबरा गए लेकिन लाइफबोट्स से बच्चों और महिलाओं को बचाने का काम शुरू हो गया। हिमखंड से टकराने के लगभग 3 घंटे बाद 15 अप्रैल की सुबह 2 बजकर 20 मिनट पर जहाज पूरी तरह से उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया।

क्या है

1. आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर जहाज था। इसकी लंबाई 882 फीट थी।
2. जहाज में हर दिन 600 टन कोयले की खपत होती थी। करीब 100 टन कोयले की राख 24 घंटों के अंदर इससे निकल कर समुद्र में जाती थी।
3. कहा जाता है कि जब यह जहाज बन रहा था उस दौरान करीब 246 इसे बनाने में जख्मी हुए थे वहीं 2 लोगों की मौत हो गई थी।
4. जहाज पर सवार 13 जोड़े हनीमून सेलिब्रेशन के लिए यात्रा पर निकले थे। टाइटैनिक की सीटी की आवाज 11 मील दूर से सुनी जा सकती थी।
5. इसे बनाने में 30 लाख से ज्यादा कीलों का इस्तेमाल किया गया था।
6. टाइटैनिक के 4 में 3 ही चिमनी काम करते थे। एक तो बस इसलिए था कि जहाज की खूबसूरती बनी रहे।

19 अप्रैल को धरती के पास से गुजरेगा बड़ा क्षुद्रग्रह

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कहना है कि 19 अप्रैल को रॉक आफ जिब्राल्टर जितना एक बड़ा क्षुद्रग्रह धरती के पास से करीब 18 लाख किलोमीटर की दूरी से सुरक्षित गुजरेगा। हालांकि इस क्षुद्रग्रह के धरती से टकराने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन इस आकार के क्षुद्रग्रह का धरती के पास से गुजरना महत्वपूर्ण काफी होगा।

क्या है

1. क्षुद्रग्रह नाम का 2014-जेओ25 है, जिसकी खोज मई 2014 में अमेरिका के एरिजोना में कैटालिना स्काई सर्वे के खगोलविदों ने की थी। यह क्षुद्रग्रह आकार में लगभग 650 मीटर (2000 फुट) का है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

2. इस समय इसके भौतिक गुणों के बारे में बहुत कम जानकारी है, हालांकि इसके प्रक्षेप पथ के बारे में काफी जानकारी है। क्षुद्रग्रह सूर्य का चक्कर लगाकर उसकी दिशा से पृथ्वी के नजदीक आएगा और 19 अप्रैल के बाद रात के समय आकाश में देखा जा सकेगा।
3. अगली बार लगभग इस आकार का क्षुद्रग्रह 2027 में धरती के करीब से गुजरेगा। 800 मीटर चौड़ा यह क्षुद्रग्रह (199-एएन10) धरती से एक चंद्र दूरी लगभग 3,80,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा।
4. आगामी 19 अप्रैल की घटना इस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने का एक बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगी। विश्वभर में खगोल विज्ञानियों की योजना दूरबीनों से इसका अध्ययन करने की है, ताकि इसके बारे में अधिक से अधिक पता चल सके।
5. इससे पहले करीब 400 साल पहले 2014-जेओ 25 धरती के इतने करीब आया था, इसके बाद यह क्षुद्रग्रह धरती के इतना नजदीक नहीं आया है और अब कम से कम सन 2600 तक धरती के इतना नजदीक आएगा।
6. नासा ने कहा है कि 19 अप्रैल को ही पैनस्टार्स नाम का धूमकेतु (सी-2015 ईआर 61) धरती के सबसे नजदीक से यानी कि 17 करोड़ 50 किलोमीटर की बहुत ही सुरक्षित दूरी से गुजरेगा।

विश्व होम्योपैथी दिवस पर दो दिवसीय सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न

विश्व होम्योपैथी दिवस पर 10 अप्रैल 2017 नई दिल्लीं में दो दिवसीय सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। समारोह की अध्येक्षता सांसद और आयुष मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के सदस्ज डॉ. मनोज रजोरिया ने की। विश्व होम्योयपैथी दिवस होम्योपैथी के जन्मंदाता जर्मन चिकित्सिक डॉ. क्रिस्टियानी फ्रेडरिक सैमुएल हनिमैन की 262 वीं जयंती के उपलक्ष में आयोजित किया गया। डॉ. क्रिस्टियानी फ्रेडरिक सैमुएल हनिमैन महान विद्वान, भाषाविद और प्रख्यातत वैज्ञानिक थे।

क्या है

1. सम्मेलन का थीम होम्योपैथी में अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाना था। सम्मेलन का आयोजन आयुष मंत्रालय की केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया।
2. इस अवसर पर आयुष मंत्री ने हनिमैन के योगदान और उनके द्वारा प्रकृति के अचूक कानून के आधार पर चिकित्सा व्यवस्था की खोज करने के बारे में बताया।
3. आयुष मंत्रालय आयुष प्रणाली में और अधिक साक्ष्य लाने और अंतर्राष्ट्रीय मान्य साधनों से प्रणाली को वैध बनाने के लिए संकल्पलबद्ध है। विश्वसनीय होम्योपैथी अनुसंधान में सीसीआरएच द्वारा लगाई गई छलांग की सराहना की।
4. शिष्टमंडल को बताया कि सीसीआरएच ने क्वांटम भौतिकी जैवइंजीनियरिंग, वाइरौलॉजी, रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थानों से सहयोग किया है।
5. इस काम में न केवल होम्यो पैथी को मान्यता मिली है बल्कि संबद्ध वैज्ञानिकों का ध्यान भी इस उपचार प्रणाली की और गया है। हमें होम्योकपैथी और नैनोविज्ञान तथा जैनोमिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने की आवश्यकता है।
6. इस अवसर पर पहली बार सीसीआरएच ने होम्योपैथी अनुसंधान में योगदान करने वालों को पुरस्कार प्रदान किया।
7. होम्योपैथिक अस्पतालों के एनएबीएच प्रमाणन सहित उच्च गुणवत्ता युक्त व अनुसंधान माध्यमों द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारियों में होम्योपैथी की भूमिका के महत्वपूर्ण कारक सहित अनुसंधान करने के लिए कॉलेज के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने तथा होम्योपैथिक अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों को विचार-विमर्श के लिए पांच सत्रों में विभक्त किया गया।

हिन्दुस्तान रत्न PSU AWARDS 2017

केंद्र सरकार ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के लिए महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न का दर्जा देने की पहल समय-समय पर शुरू की और उसे विस्तार दिया। ताकि पीएसयू ज्यादा वित्तीय स्वायत्तता और पेशेवर रुख के साथ काम कर सकें। इससे इन कंपनियों के शेयरों का बेहतर मूल्यांकन भी होगा।

क्या है

1. केंद्र सरकार ने वर्ष 1997 में अच्छा प्रदर्शन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को खास पहचान देने के उद्देश्य से अकबर के नवरत्नों की तर्ज पर 'नवरत्न' खिताब की शुरुआत की।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

2. इन कंपनियों को वैश्विक बाजार में ज्यादा बेहतर ढंग से प्रदर्शन करने के लिए केंद्र से खास मदद भी दी।
3. 2500 करोड़ का वार्षिक शुद्ध लाभ 3 साल तक जरूरी महारत्न के लिए।
4. 60 अंक जरूरी 100 में से केंद्र के तय छह मानकों के आधार पर नवरत्न के लिए।
5. 30 करोड़ का शुद्ध लाभ जरूरी तीन में से किसी एक साल में मिनीरत्न के लिए।
6. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन कंपनी सामाजिक कार्यों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती है। हाल ही में कंपनी के मुख्य प्रबंध निदेशक आई.एस. झा (काली जैकेट) ने स्वच्छ भारत कोष के लिए वित्त मंत्रालय को चेक सौंपा।
7. देश के 17 नवरत्नों में एक पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन का कर के बाद शुद्ध मुनाफा वर्ष 2015-16 में 21 फीसदी बढ़कर 6,027 करोड़ रुपये रहा। इस दौरान कंपनी का टर्नओवर भी 20 फीसदी बढ़कर 21 हजार 281 करोड़ रुपये से अधिक रहा।

सफलता की सीढ़ियां

1. 20% बढ़ा पॉवर ग्रिड का मुनाफा 2016-17 की तीसरी तिमाही में
2. 1930 करोड़ रहा शुद्ध मुनाफा 2016-17 में अक्तूबर-दिसंबर की तिमाही में
3. पिछले साल इसी दौरान 1606 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था

1989 में हुई स्थापना

1. पॉवर ग्रिड की स्थापना 23 अक्तूबर 1989 को पांच हजार करोड़ रुपये की पूंजी के साथ हुई थी।
2. अब इसकी परिसंपत्ति 1784 अरब रुपये से ज्यादा है।
3. देश के सबसे बड़े ग्रिड के साथ इसका ट्रांसमिशन नेटवर्क एक लाख 34 हजार किलोमीटर से ज्यादा का है।

महारत्न

1. महारत्न का खिताब पाने की योग्यता के लिए एक कंपनी का वर्ष में औसत कारोबार 20 हजार करोड़ रुपये होना चाहिए जो तीन साल पहले 25 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था।
2. कंपनी का औसत वार्षिक कुल मूल्य 10 हजार करोड़ रुपये होना चाहिए। महारत्न दर्जा प्राप्त पीएसयू अपनी परियोजना के कुल मूल्य के 15 फीसदी हिस्से तक निवेश करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन यह निवेश पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. भारत की सात कंपनियों को महारत्न का दर्जा मिला हुआ है। ओएनजीसी, एनटीपीसी, गेल इंडिया, कोल इंडिया, सेल, भेल और इंडियन ऑयल को महारत्न का दर्जा मिला है।

नवरत्न

1. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्न को एक हजार करोड़ रुपये या एक परियोजना में उसके कुल मूल्य का 15 फीसदी तक बिना सरकारी मंजूरी के निवेश करने का क्षमता प्रदान करता है।
2. एक साल में ऐसी कंपनियां कुल मूल्य का 30 फीसदी तक खर्च कर सकती हैं परंतु यह एक हजार करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। मौजूदा दौर में पॉवर ग्रिड कारपोरेशन समेत 17 नवरत्न हैं।
3. देश में 73 मिनीरत्न हैं। मिनीरत्न बनने के लिए पीएसयू तीन साल लगातार लाभ में हों। इन तीन वर्षों में से एक में कम से कम 30 करोड़ रुपये का पूर्व कर लाभ होना चाहिए।

केरल में इन्टरनेट की सुविधा का अधिकार

भारत के सबसे शिक्षित राज्य केरल ने हाल ही में सभी नागरिकों के लिये भोजन, शिक्षा और पानी के जैसे ही इंटरनेट एक्सेस को मौलिक मानवाधिकार घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य ने अपने बजट में एक योजना पेश की है जिसका लक्ष्य है कि बेहद सस्ते दामों में सभी को इंटरनेट कनेक्शन देने के साथ 20 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त में इसकी सुविधा दी जाए और इसके लिये केरल सरकार 'केरल इंफ्रास्टक्चर फंड' से 1000 करोड़ का लोन ले रही है।

क्या है

1. आज के तेजी से बढ़ रहे डिजिटल दौर में जब सरकार कैशलेस इकॉनमी की तरफ बढ़ने के अभियान के साथ ही ई-गवर्नेंस और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है तो ऐसे में इंटरनेट तक सबकी पहुँच ज्यादा जरूरी हो जाता है।
2. विदित हो कि संयुक्त राष्ट्र ने भी यह कहा है कि विश्व के सभी देशों को इंटरनेट की सुविधा को बुनियादी मानवाधिकार घोषित कर देना चाहिये, उल्लेखनीय है कि इसे भारतीय संविधान में घोषित मूल अधिकार के तहत नहीं कानूनी अधिकारों के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिये।
3. विश्व के कई देश पहले ही इस व्यवस्था को अपना चुके हैं।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

4. साल 2010 में स्वीडन दुनिया का पहला ऐसा देश बना था जहाँ हाई स्पीड इंटरनेट को प्राथमिक कानूनी अधिकार के तौर पर शामिल किया गया था।
5. इसके बाद कनाडा ने भी पिछले साल स्वीडन की तर्ज पर फैसला किया कि हर नागरिक को कम से कम 50 एमबीपीएस की स्पीड से इंटरनेट की सुविधा मिलनी चाहिये।

राष्ट्रपति ने स्कोप पुरस्कार प्रदान किए

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 11 अप्रैल, 2017 नई दिल्ली में आयोजित 8वें सार्वजनिक क्षेत्र दिवस समारोह के दौरान लोक उद्यम स्थायी सम्मेलन (स्कोप) पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि इस दिन को जश्न के रूप में मनाना हमारे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा किए गए अमूल्य योगदान की स्वीकृति है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद से पीएसई को हमारे देश में औद्योगिकीकरण के वाहन के रूप में चुना गया था। उन्होंने कहा कि वह इस बात में दृढ़ विश्वास रखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रासंगिकता का काफी महत्व है। उन्होंने कहा कि वह इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि सीपीएसई भविष्य में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखेंगे और नई चुनौतियों का सामना करेंगे।

क्या है

1. अपने देश में 2 करोड़ रुपये के निवेश के साथ केवल पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसई) की शुरुआत की थी। हालांकि, इन वर्षों के दौरान उनमें शानदार वृद्धि दर्ज की गयी। वर्ष 2015-16 के दौरान उनके समग्र शुद्ध लाभ में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह सराहनीय प्रदर्शन है क्योंकि वैश्विक वित्तीय और आर्थिक परिदृश्य तथा औद्योगिक जलवायु अनुकूल नहीं होने के बावजूद भी वे अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं।
2. राष्ट्रपति ने कहा कि वह कई अवसरों पर स्कोप प्रणाली से जुड़े थे। उन्होंने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और भविष्य में उनके सफलता की कामना की।
3. इस अवसर पर भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री श्री अनंत जी गीते, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो; सार्वजनिक उद्यम विभाग की सचिव श्रीमती सीमा बहुगुणा और स्कोप के अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश भी मौजूद थे।

वृक्षों के सम्बन्ध में प्रथम वैश्विक आँकड़े जारी

लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति संरक्षण उद्यान द्वारा 5 अप्रैल 2017 को वृक्षों के सम्बन्ध में प्रथम वैश्विक आँकड़े जारी किये गए। इन आँकड़ों के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि पृथ्वी पर वृक्षों की कुल 60,065 प्रजातियाँ हैं तथा इनमें से 9,600 प्रजातियाँ विलुप्तिकरण के खतरे से जूझ रही हैं।

क्या है

1. लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति संरक्षण उद्यान (Botanic Gardens Conservation International- BGCI) विश्व के 2,500 वनस्पति संरक्षण उद्यानों का प्रतिनिधित्व करता है।
2. उद्यान ने इस सूची को बनाने में 500 प्रकाशित स्रोतों के आँकड़ों का प्रयोग किया।
3. वृक्षों की 60,065 प्रजातियों में से मात्र 20,000 प्रजातियों को ही संरक्षण का दर्जा प्राप्त है। इन 20,000 प्रजातियों में से भी 9,600 प्रजातियाँ वनोन्मुलन और अत्यधिक दोहन के कारण विलुप्तिकरण के खतरे से जूझ रहीं हैं। विदित हो कि वर्तमान में वृक्षों की लगभग 10,000 प्रजातियाँ विलुप्ति के कगार पर हैं।
4. इस अध्ययन में लगभग 300 प्रजातियों की पहचान गंभीर संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में की गई है क्योंकि जंगलों में इन प्रजातियों के केवल 50 वृक्ष ही शेष बचे हैं।
5. इस अध्ययन में पाया गया कि एक देश में वृक्षों की आधे से अधिक (58%) प्रजातियाँ स्थानिक थी। इस अध्ययन में यह सामने आया कि ये सभी मौसमी घटनाओं अथवा मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले वनोन्मूलन जैसे खतरे के प्रति संवेदनशील थीं।
6. इस सूची को प्रकाशित करने के पीछे बी.जी.सी.आई. का मुख्य उद्देश्य उन लोगों के लिये आवश्यक आँकडे व साधन उपलब्ध कराना था जो वृक्ष की दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं।
7. इस अध्ययन का एक मुख्य लक्ष्य वृक्षों की प्रजातियों को भू-संदर्भित करना है जो संरक्षणकर्ताओं को विशिष्ट प्रजातियों के स्थान का पता लगाने में मदद करेगा।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

8. इनके स्थान की जानकारी मिलने से (जैसे-ये वृक्ष कौन से देश में होते हैं) इनका संरक्षण किया जा सकेगा। यह अध्ययन लाभकारी सिद्ध हो सकता है परन्तु इसके लिये वृक्षों की प्रजातियों का मूल्यांकन कर इनकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

संविधान पीठ करेगा व्हाट्सएप मामले की सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया दिग्गज 'व्हाट्सएप' की निजता नीति के मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया जो मामले पर सुनवाई करेगी। हालाँकि इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजे जाने का विरोध करते हुए व्हाट्सएप की तरफ से मामले के पैरवीकार अधिवक्ता ने दलील दी कि वर्ष 1962 में खड़क सिंह मामले में 6 जजों की एक संविधान पीठ ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार, असीमित नहीं है।

पृष्ठभूमि

1. वर्ष 2017 के आरम्भ में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि व्हाट्सएप ने अपने सहयोगी फेसबुक से, यूजर्स की निजी जानकारियाँ साझा की हैं और यह व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन है।
2. विदित हो कि 2016 में लागू निजता की नई नीति के तहत व्हाट्सएप, फेसबुक के साथ उपयोगकर्ताओं के डेटा साझा करता है। याचिकाकर्ता का कहना था कि इससे न सिर्फ उपभोक्ता का ब्यौरा, बल्कि उसकी निजी बातचीत भी गलत हाथों में जा सकती है।
3. प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया था कि आप मुफ्त सेवा का उपयोग करते हुए निजता के अधिकारों का दावा नहीं कर सकते। हाँलाकि बाद में जस्टिस खेहर और जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड़ की बेंच ने इस मामले पर सरकार, भारतीय दूरसंचार नियामक और व्हाट्सएप तथा फेसबुक को नोटिस जारी कर इसका जवाब मांगा था।
4. याचिका में कहा गया है कि भारत सरकार को अनुच्छेद 19 के तहत उसके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिये। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि भारतीय दूरसंचार नियामक इस संबंध में उपयुक्त कदम उठाने में विफल रहा है।

क्यों है विवाद?

1. दुनिया भर में चर्चित और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मैसेंजिंग सेवा 'व्हाट्सएप' ने 26 सितंबर 2016 से उपयोगकर्ताओं की जानकारी फेसबुक के साथ साझा करने का फैसला किया था।
2. दरअसल, तब उपयोगकर्ताओं की जानकारी फेसबुक के साथ साझा करने के मामले में ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने मैसेंजिंग साइट व्हाट्सएप से कहा था कि वह 25 सितंबर 2016 से पहले के अपने यूजर्स की जानकारियाँ फेसबुक से साझा नहीं करे।
3. विदित हो कि इस तारीख से व्हाट्सएप की निजता की नई नीति लागू हो गई है अत: नई नीति लागू होने के बाद इस मैसेंजिंग साइट के यूजर्स बनने वाले लोगों की जानकारियाँ साझा की जा सकती हैं।

संयुक्त राष्ट्र में मनाई जाएगी अंबेडकर जयंती

संयुक्त राष्ट्र में पहली बार भारतीय संविधान के रचयिता बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। इस जयंती में सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए असमानताओं से लड़ने पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए असमानताओं से लड़ने पर ध्यान दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मिशन ने यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स (यूएनडीईएसए) और यूएस एनजीओ फाउंडेशन फॉर ह्यूमन होरायजन के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है।

क्या है

1. उप सचिव जनरल अमिना जे मोहम्मद समारोह में प्रमुख वक्ता होंगे, जिसमें सामाजिक और वित्तीय समावेश के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने पर एक पैनल चर्चा होगी।
2. इसका संचालन कोलंबिया विश्वविद्यालय में हेल्थकेयर इनोवेशन टेक्नोलॉजी लैब (एचआईटीएलबी) के अध्यक्ष स्टेन काचनोव्स्की द्वारा किया जाएगा।
3. कैथरीन न्यूमैन मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय के कुलपति, ग्लोबल गवर्नमेंट उद्योग के आईबीएम के महाप्रबंधक जूलिया ग्लिडेन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यूएस ऑपरेशंस के कंट्री हेड, द इंडियन नेटवर्क के संस्थापक रवि नार्वेकर और गूगल में क्रिएटिव हेड ऑलिविर रबेस्चलाग इसके पैनलिस्ट होंगे।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

फेक न्यूज की रोकथाम हेतु वैश्विक पहल

तकनीकी उद्योगों और शैक्षणिक संगठनों ने नकली समाचारों या 'फेक-न्यूज' के प्रसार को रोकने, समाचार साक्षरता को बढ़ावा देने और पत्रकारिता की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिये एक साथ कार्य करने की पहल की है। इस कार्य के लिये वैश्विक स्तर पर + 14 मिलियन की प्रारंभिक योजना बनाई गई है।

इस पहल में शामिल प्रमुख संगठन

1. आरहस विश्वविद्यालय (Aarhus University) डेनमार्क के रचनात्मक संस्थान,
2. नीदरलैंड्स स्थित यूरोपीय पत्रकारिता केंद्र,
3. फण्डैसियन गेब्रियल गार्सिया मार्केज पैरा अल न्यूवो पेरीडिस्मो इबेरोमेरिकानो (Fundacion Gabriel Garcia Marquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano) कोलंबिया,
4. हैम्बर्ग मीडिया स्कूल (Hamburg Media School) और हेंस-ब्रेडो-इंस्टीट्यूट (Hans-Bredow-Institute) जर्मनी,
5. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पॉलिस मीडिया डिपार्टमेंट (Polis media department),
6. फ्राँस का विज्ञान पो विश्वविद्यालय (France's Sciences Po university),
7. एशिया में हांगकांग स्थित प्रकाशक सोसाइटी (Hong Kong-based Society of Publishers in Asia),
8. ऑस्ट्रेलिया में वाक्ले फाउंडेशन (Walkley Foundation),
9. यूनेस्को (UNESCO).

क्या है

1. तकनीकी उद्योग और शैक्षणिक संगठनों की वैश्विक गठबंधन ने नकली समाचार (थंम छमू) से निपटने और पत्रकारिता की सार्वजनिक समझ में सुधार के लिये 3 अप्रैल 2017 को एक साथ काम करने की योजना बनाई।
2. इस वैश्विक पहल को 'न्यूज इंटिग्रिटी इनिशिएटिव' (News Integrity Initiative) नाम दिया गया।
3. इस योजना को + 14 मिलियन के साथ प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। जिसमें फेसबुक, फोर्ड फाउंडेशन (Ford Foundation), मोजिला (डब्रपससं) एवं न्यूयार्क यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता स्कूल इत्यादि प्रमुख सहभागी होंगे।
4. फेसबुक और गूगल द्वारा पहले से ही गलत जानकारी को बढ़ावा देने वाली समाचार साइटों पर विज्ञापनों की आय में कटौती के लिये कदम उठाए गए हैं।
5. अन्य प्रमुख सहयोगियों में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट्स, न्यूज लिटरेसी प्रोजेक्ट, ट्रस्ट प्रोजेक्ट और जनसंपर्क समूह वेबर शेंडविक (Weber Shandwick) शामिल हैं।

राज्यपाल की भूमिका पर केंद्रित रही अंतरराज्यीय परिषद

राजनीतिक अस्थिरता के दौरान राज्यपाल की भूमिका, कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र व राज्यों के बीच बनते बिगड़ते संबंध और वित्तीय प्रभाव जैसे विषयों पर अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति ने विस्तार से विचार विमर्श किया गया। गैर भाजपा शासित राज्यों की ओर से सरकार को सुझाव दिया गया कि राज्यपालों की नियुक्ति में उनके नामों पर ही विचार किया जाना चाहिए, जो किसी भी राजनीतिक विवाद से परे हों। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में अरुणाचल प्रदेश से लेकर गोवा तक ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिसे लेकर विपक्ष का रुख आक्रामक रहा है। मामला कोर्ट तक पहुंचा। ऐसे मे अंतरराज्यीय परिषद की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्र में खुशहाली और संपन्नता तभी आएगी, जब शांति व स्थिरता कायम रहेगी।

क्या है

1. भारत की विविधता में एकता ही हमारी विशेषता है। सिंह ने कहा कि केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग के लिए विश्वास और परस्पर आत्मीयता ही मूल आधार है। हमे राष्ट्रीय विकास के लिए संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच से बाहर निकलना होगा। रविवार को हुई यह बैठक अंतरराज्यीय परिषद की 16 जुलाई 2016 की हुई बैठक से आगे की है।
2. आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे वहां के वित्त मंत्री वाई.कृष्णनुडु ने कहा 'कई राज्यों ने राज्यपाल की योग्यता के बारे में अपना विचार रखा, जिसके मुताबिक राज्यपाल को निष्पक्ष और राजनीति से ऊपर होना चाहिए।'
3. पंछी आयोग को 2005 में गठित किया गया, जिसकी रिपोर्ट 2010 में पेश कर दी गई थी। आयोग की रिपोर्ट के कुल सात खंड हैं, जिसमें केंद्र व राज्य के बीच संबंध, संवैधानिक गवर्नेंस व प्रबंधन, केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय संबंध और योजना, स्थानीय निकाय व उसके अधिकार, आंतरिक सुरक्षा, क्रिमिनल जस्टिस, पर्यावरण प्राकृतिक संपदा व बुनियादी ढांचा, सामाजिक आर्थिक विकास, पब्लिक पालिसी व सुशासन जैसे विषयों को शामिल किया गया है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

4. स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में पंछी आयोग के दूसरे व तीसरे खंड में उठाये गये विषयों की समीक्षा की गई। आयोग की रिपोर्ट के दूसरे खंड में केंद्र व राज्य के बीच संवैधानिक प्रावधानों का विस्तार से जिक्र किया गया है, जिसमें राज्यपालों की भूमिका के साथ केंद्रीय बलों की तैनाती और संघीय शक्ति संतुलन का ब्यौरा दिया गया है। इसके अलावा भी कई अहम मुद्दों को इसमें रखा गया है।
5. आयोग की सिफारिशों के तीसरे खंड में केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को विस्तार से रखा गया है। इसमें राज्यों के लिए राजकोष मुहैया कराना, अति चर्चित जीएसटी और अन्य तरह के वित्तीय संबंधों का जिक्र किया गया है। इस खंड में केंद्र व राज्य के संबंधों में संवैधानिक प्रावधानों के तहत सुशासन की मुश्किलों को घटाने पर जोर दिया गया है।
6. पंछी आयोग की कुल 273 सिफारिशों में से 132 पर विचार किया गया। जबकि बचे खंडों पर स्टैंडिंग कमेटी की अगली बैठक में चर्चा होगी। इसमें जीएसटी से उपजने वाली चुनौतियों, 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट, नीति आयोग के गठन और केंद्र की प्रायोजित योजनाओं पर अमल जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
7. गृहमंत्री सिंह की अध्यक्षता में अंतरराज्यीय परिषद की 11वीं स्टैंडिंग कमेटी की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय वित्त व प्रतिरक्षा मंत्री अरुण जेटली और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, उड़ीसा के नवीन पटनायक और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक सरकार समेत आंध्र प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के मंत्रियों ने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा परिषद से जुड़े कई आला अफसरों ने हिस्सा लिया।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)